



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पार्यायिकार



साइबर अपराधों से
निपटने को एआई का
उपयोग करें एजेंसियां
राष्ट्रीय-9

www.dailypioneer.com

रेलवे को पटरी से उतारने की साजिश लगातार जारी

दीपक कुमार झा | नई दिल्ली

भारतीय रेलवे पिछड़े डेढ़ साल से पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर रखने से लेकर लोहे की छड़ें, बड़े-बड़े पत्थर, कंक्रीट के स्लैब और पेड़ के तने रखने तक तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों से जूझ रहा है, जिसके कारण रेलवे को यात्री और मालगाड़ी बेहतर संचालन को लेकर खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुओं ने बताया कि केंद्र ने राज्यों समेत सभी हितधारकों से रेलवे को अस्थिर करने के नापाक मंसूवों को नाकाम करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है, खास तौर पर मध्य उत्तर प्रदेश

और राजस्थान के कुछ हिस्सों वाले एक सघन क्षेत्र में। इस तरह की बढ़ती गतिविधियों के पैटर्न के बारे में शीर्ष स्तर पर जांच भी की जा रही है, जिसकी शुरुआत स्कूलों में बम धमाकों, उसके बाद शॉपिंग मॉल और अब रेलवे में इसी तरह की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना फरहनुल्लाह घोरी, जिसका 2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले और बंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट में हाथ था उसने भारत में आतंकी स्त्री पर सेल को एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उनसे ट्रेनों, पेट्रोलियम पाइपलाइनों और हिंदू नेताओं पर

हमले करने का आग्रह किया था। हाल ही में हुए रेल हादसों की भी इसी एंगल से जांच की जा रही है। राजस्थान में अजमेर के पास मंगलवार को रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की एक और कोशिश के साथ ही अगस्त 2024 से रेलवे ट्रेक पर तोड़फोड़ की कुल 18 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि जून 2023 से 28 ऐसे गंभीर तोड़फोड़ के मामलों की जांच चल रही है। कुछ तोड़फोड़ की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सीबीआई कर रही है। हाल के हफ्तों में राजस्थान में ट्रेन को पटरी से उतारने की यह तीसरी कोशिश है। इससे पहले 28 अगस्त

रेल पटरियों पर तोड़फोड़	
अक्टूबर 2023	चित्तौड़गढ़ में रेलवे ट्रेक पर लोहा और पत्थर
फरवरी 2024	पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी
जून 2024	पश्चिम बंगाल में सिमल लाइट को कागज से ढक दिया
जुलाई 2024	यूपी में यूट्यूबर 'इंडियन हैकर' ने रेलवे ट्रेक पर गैस सिलेंडर, केची जैसी चीजें रख वीडियो रिकॉर्ड कर चैनल पर अपलोड किया
जुलाई 2024	पश्चिम बंगाल में 'उर्स मेला' के 400-500 लोगों ने ट्रेन रोकी
अगस्त 2024	यूपी में ड्यूटी के बाद घर जाते समय स्टेशन मास्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा को गोली मार दी गई
अगस्त 2024	राजस्थान में सोमेट कंक्रीट से पटरी को ढका
अगस्त 2024	झारखंड में 100 पैंडोल क्लिप चोरी

को छबड़ा बारा में मालगाड़ी की पटरी पर स्क्रैप मेटल फेंका गया था

और 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद-जोधपुर वंदे भारत ट्रेक

कानपुर में चल रही जांच में शामिल हो गई है। कानपुर पुलिस ने इस

मामले में दो स्थानीय हिस्ट्रीशीटों समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है और एक विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। यह दल यह अध्ययन करेगा कि क्या कानपुर में हाल ही में हुई साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना से कोई समानता है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पार्यायिकार से कहा, वरिष्ठ अधिकारी मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है, बल्कि दिसंबर 2017 में तोड़फोड़ के मामलों में असाधारण बढ़ोतरी के साथ एक समान पैटर्न देखा गया था, जिसमें लगभग 18 घटनाएं दर्ज की गई थीं। तत्कालीन

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर दुर्घटनाओं को एनआईए द्वारा विस्तृत जांच की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने 'बाहरी लोगों' द्वारा अपराधिक हस्तक्षेप का संभावना' की घटनाओं को सूचीबद्ध किया था। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आईएसआईएस के लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, जांच एजेंसियों ने 219 कैमरों से फुटेज एकत्र की है और कानपुर ट्रेन को पटरी से उतारने के प्रयास के संबंध में 100 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की है।



मणिपुर की राजधानी इफाल में मंगलवार को प्रदर्शन करते छात्र। राज्य के तीन जिलों में अशांति के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है

इफाल घाटी में शांति के लिए प्रदर्शन के बाद मणिपुर में लगा कर्फ्यू

पायनियर समाचार सेवा | इफाल

मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद राज्य के तीन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं पांच दिनों के लिए निलंबित कर दी हैं। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि यह निर्णय तत्काल, नफरती भाषण और नफरती वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। मणिपुर राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, ऐसी आशंका है कि कुछ असांभालित तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली छवियां, अभद्र भाषा और रूपावली वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है, भड़काऊ सामग्री और अफवाहों के परिणामस्वरूप, जो सोशल मीडिया, मोबाइल सेवाओं, एसएमएस और डॉलर सेवाओं पर संदेश लोगों तक प्रसारित किया सकता है। जिससे सार्वजनिक, निजी संपत्ति को नुकसान, शांति और सद्भावना में गड़बड़ी का खतरा है। राष्ट्र-विरोधी और असांभालित तत्वों की साजिशों

और गतिविधियों को विफल करने तथा शांति और सांस्कृतिक सद्भाव बनाए रखने और सार्वजनिक, निजी संपत्ति को किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या खतरों को रोकने के लिए, जनहित में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि पर ब्लाट्सएप, नफरती भाषण और नफरती वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गलत सूचनाओं और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोकना और आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को एकत्र करने के लिए बड़े पैमाने पर एसएमएस भेजना शामिल है। जो आगजनी हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिस होकर जान-माल की हानि पहुंचा सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है, मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में 10 सितंबर को अपराहन 3 बजे से 15 सितंबर को अपराहन 3 बजे तक पांच दिनों के लिए लीज लाइन, वीसैट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को छात्र और महिला प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक और राज्य के सुरक्षा सलाहकार को पद से हटाने की मांग

को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प होने पर सुरक्षा बलों ने 'ऑसू' गैस के गोले दारे। इससे एक दिन पहले सोमवार से ख्यामबंद महिला बाजार में डेरा डाले सैकड़ों छात्र बी टी रोड के जरिए राजभवन की ओर बढ़ने करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें कोण्डेस भवन के पास रोक दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक विरोध रैली निकाली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूँका। मणिपुर सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और शीबल में भारतीय नागरिक सुरक्षा सलाहकार को हटाने की अपनी मांग को लेकर अपने प्रदर्शन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने में असमर्थ हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जिले में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों में से कम से कम एक कर्मी की जांच में गोली लगी थी। इस बीच विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने इफाल के ख्यामबंद महिला बाजार में लगाए गए शिविरों में रात बिताई। छात्र नेता चौधरी विक्टर सिंह ने मंगलवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, उन्होंने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपनी छह मांगों पर जवाब देने के लिए 24 घंटे की समयसीमा दी है। समयसीमा समाप्त करने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे।

पिछले साल एक सितंबर से लोगों के अपने-अपने आवासों से बाहर आगमन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। पहले 10 सितंबर के लिए कर्फ्यू में छूट तड़के पांच बजे से शाम 10 बजे तक थी, लेकिन नवीनतम आदेश ने इसे समाप्त कर दिया। हालांकि, मीडिया, बिजली, अदालत और स्वास्थ्य समेत आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। इफाल के दोनों जिलों में यह आदेश ऐसे समय में आए हैं जब मणिपुर में छात्र राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की अपनी मांग को लेकर अपने प्रदर्शन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने में असमर्थ हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जिले में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों में से कम से कम एक कर्मी की जांच में गोली लगी थी। इस बीच विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने इफाल के ख्यामबंद महिला बाजार में लगाए गए शिविरों में रात बिताई। छात्र नेता चौधरी विक्टर सिंह ने मंगलवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, उन्होंने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपनी छह मांगों पर जवाब देने के लिए 24 घंटे की समयसीमा दी है। समयसीमा समाप्त करने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे।

भाजपा ने अमेरिका में सिख समुदाय पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को घेरा



पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौर पर कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। यहां उनके दिए गए बयान सुर्खियां बन रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस तीखा हमला किया जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में संबेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिका में राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सच बोलने से भाजपा का पुरा तंत्र घबराया और लड़खड़ाया हुआ है। लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करता रहेगा। राहुल वर्तमान में अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। उनका पहला पड़ाव डलास था जो शनिवार को शुरू हुआ और वह सोमवार को वाशिंगटन डीसी पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल की टिप्पणी भयावह है, क्योंकि उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए विदेश में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूट फैलाने की कोशिश की। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की निंदा करना है। भाजपा या नरेन्द्र मोदी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना भारत की निंदा करना है। यह (धारणा) गलत है। खेड़ा ने कहा, भारत के राष्ट्र निर्माताओं की निंदा जब प्रधानमंत्री करते हैं, तो किसकी निंदा करते हैं। उस समय हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनकों क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा, जहां तक बात चुनावों की निष्पक्षता की है, तो एक स्वतंत्र संस्था ने अपने आंकड़ों खे कि कैसे 79 लोकसभा सीट पर गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर कहते हैं कि लोगों को भारतीय धरती पर पैदा होने पर शर्म आती है, तो वह क्या था। जब वे विदेश में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलते हैं, तो वह क्या था। भाजपा द्वारा राहुल गांधी की सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी की आलोचना करने के लिए 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला दिए जाने पर उन्होंने कहा कि दंगों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। उनकी पार्टी हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है जो लोग आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, वे कल सिखों की पगड़ी के लिए भी आंदोलन चलाएंगे। इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा कबसे भारत हो गई कि भाजपा की निंदा करने का मतलब भारत की निंदा करना है। भाजपा या नरेन्द्र मोदी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना भारत की निंदा करना है। यह (धारणा) गलत है। खेड़ा ने कहा, भारत के राष्ट्र निर्माताओं की निंदा जब प्रधानमंत्री करते हैं, तो किसकी निंदा करते हैं। उस समय हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनकों क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा, जहां तक बात चुनावों की निष्पक्षता की है, तो एक स्वतंत्र संस्था ने अपने आंकड़ों खे कि कैसे 79 लोकसभा सीट पर गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर कहते हैं कि लोगों को भारतीय धरती पर पैदा होने पर शर्म आती है, तो वह क्या था। जब वे विदेश में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलते हैं, तो वह क्या था। भाजपा द्वारा राहुल गांधी की सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी की आलोचना करने के लिए 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला दिए जाने पर उन्होंने कहा कि दंगों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। उनकी पार्टी हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है जो लोग आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, वे कल सिखों की पगड़ी के लिए भी आंदोलन चलाएंगे। इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है।

हरियाणा : भाजपा ने दूसरी सूची जारी की, छह विधायकों का टिकट कटा

राजेश कुमार | नई दिल्ली

भाजपा ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में दो मंत्रियों समेत छह मौजूदा विधायकों के नाम काट दिया गया है। भाजपा ने कांग्रेस की ओलंपियन उम्मीदवार विनेश फोगट के खिलाफ जुलाना से कैप्टन योगेश बेरारी को मैदान में उतारा है, जबकि दो पूर्व मंत्रियों कृष्ण कुमार बेदी और मनीष प्रोवर को क्रमशः नरवाना और रोहतक सीटों से मैदान में उतारा है। सूची में दो मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनाहाना से एजाज खान। इसके साथ ही भाजपा ने 87 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जबकि तीन क्षेत्रों में पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, वे हैं फरीदाबाद-पुनआबी, सिरसा और महेंद्रगढ़। पार्टी के पिहोवा उम्मीदवार सदावर कमलजीत सिंह अजराना की जगह जय भगवान शर्मा को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने स्थानीय नेताओं के विरोध का हवाला देते हुए पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने से अपनी असमर्थता जताया है। उन्होंने उन्नीषीन मामले में आरोपी मौजूदा विधायक और पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के नाम को हटाकर अजराना का नाम पहली सूची में शामिल किया गया था। भाजपा ने निवर्तमान विधानसभा में बावल का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री बनवारी लाल का टिकट काटते हुए उनकी जगह कृष्ण कुमार को मैदान में उतारा है। स्कूली शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जो कि बधकल की निवर्तमान विधायक का भी टिकट कट गया है। इस सीट के लिए धनेश अदलखा को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने पूर्व मंत्रियों कृष्ण कुमार बेदी, मनीष प्रोवर और ओम प्रकाश यादव को क्रमशः नरवाना, रोहतक और नारनौल सीटों से मैदान में उतारा है। इस सूची में होडल (एससी) विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डगर, (शेष पृष्ठ 9)

सीताराम येचुरी की हालत गंभीर, एमएस में भर्ती

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी की हालत गंभीर है और उन्हें यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमएस) में कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया है। उनकी पार्टी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार, 72 वर्षीय एचुरी का एमएस को गहन चिकित्सा इकाई में तीव्र श्वसन नली संक्रमण का उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों की एक टीम एचुरी के स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रख रही है।

आईएफ अफसर ने वरिष्ठ के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की

पायनियर समाचार सेवा | जम्मू-कश्मीर

श्रीनगर में तैनात 26 वर्षीय फ्लाईंग ऑफिसर ने न्याय की मांग करते हुए बडगाम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को कथित यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना का मामला पेशान करने लगा है। अपनी शिकायत में, पेशान फ्लाईंग ऑफिसर ने पांच अन्य अधिकारियों पर जांच को गलत तरीके से करने, पीछा करने, उत्पीड़न और मानसिक यातना देने का भी आरोप लगाया है। फ्लाईंग ऑफिसर ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि उत्पीड़न का उसके

मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वह लगातार डर में जी रही है। चौबीस घंटे जांच के दायरे में हैं और मेरा सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पीड़िता ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को अपनी शिकायत में कहा उत्पीड़न उसे आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। वह पूरी तरह से असहाय महसूस हो और दैनिक जीवन को जारी रखने में असमर्थ है। मेरे सामाजिक मेलजोल पर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है और हतोत्साहित किया जाता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मामले में नाम दर्ज भारतीय वायु सेना (शेष पृष्ठ 9)

जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों पर हर दिन 20 किमी तक नहीं लगेगा शुल्क

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली से लैस निजी वाहनों के मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के रूप में अधिसूचित नए



नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को छोड़कर किसी अन्य वाहन का

चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थाई पुल, बाईपास या सुरंग के उसी खंड का उपयोग करता है, उससे जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि उसने फास्टेग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में सुनिश्चित राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह-आधारित टोल संग्रह प्रणाली को पायलट आंदोलन पर लागू करने का फैसला किया है। जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के शेष पृष्ठ 9)

बारामूला सांसद रशीद को मिली अंतरिम जमानत

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में मंगलवार को लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को दो अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इंजीनियर रशीद उर्फ शेख अब्दुल रशीद ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बार्कमुला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद को राहत प्रदान की, जिसने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। पांच जुलाई को अदालत ने रशीद को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए हिरासती पैराल दे दी थी। (शेष पृष्ठ 9)

‘सेमिकॉन इंडिया’ आज से शुरू, पीएम करेंगे उद्घाटन

विश्व की सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कंपनियां आएंगी, 2026 तक 55 बिलियन का होगा कारोबार

सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे

पर्यायनियर समाचार सेवा | नोएडा

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोस मार्ट में सेमीकॉन इंडिया-2024 होने का रहा है। ये आयोजित 11 से 13 सितंबर तक होगा। इसमें दुनिया भर की लीडिंग मैनुफैक्चरिंग कंपनियां प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगी। ये आयोजित इसलिए जरूरी है कि विषय के अनुसार 2026 तक सेमीकंडक्टर का कारोबार 55 बिलियन डॉलर से अधिक का होगा। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए सेमी और मेसे मुएनचेन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया-इंग्लैंडसीआईएए के साथ इस कार्यक्रम के



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

लिए साझेदारी कर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 के शेड्यूल के अनुसार, 11 से 13 सितंबर तक तीनों दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। जिसमें दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग अपने स्टॉल लगाएंगे। पहले दिन 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी-2024 इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रीनिका इंडिया के साथ आयोजित किया

जा रहा है। ये दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मेले हैं। इसमें विभिन्न देशी और विदेशी कंपनियां शामिल होने जा रही है। यहां के स्थानीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। निवेश के नजरिया को समझेंगे।

भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम को देखेंगे, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के विस्तार के नए अवसर मिल सकें। देश में तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने और घरेलू मानी को पूरा करने के लिए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल) ने एएमडी, अल्फाड मटेरियल्स और माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनियों को अपने चिप क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है।

सरकार की भी मंशा है कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रदेश को कई अन्य सेक्टर की तरह सेमीकंडक्टर उद्योगों का भी हब बनाया जा सके। ऐसा होने पर रोजगार के मार्ग बनेंगे। यूपी सेमीकंडक्टर नीति के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कैपिटल सब्सिडी पर 50

प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। पॉलिसी में कंपाउंड सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, एटीएमपी, ओएसपीटी के लिए 75 प्रतिशत की लेंड रिबेट भी प्रदान की गई है।

डुअल ग्रिड नेटवर्क के साथ ही 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 को छूट प्रदान की जा रही है। स्टॉप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट और प्रति वर्ष 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 7 करोड़ रुपए) दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। देश में 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग कंपनियां अपनी युनिट संचालित कर रही है। जिसके चलते प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग का हब बन गया है।

यही नहीं प्रदेश मोबाइल मैनुफैक्चरिंग का भी हब है। प्रदेश देश की कुल मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में 65 प्रतिशत का योगदान देता है। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश फैबलेस सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम में भी राइजिंग स्टार के तौर पर उभर रहा है। यहां लीडिंग ग्लोबल चिप डिजाइन और आरएंडडी कंपनियों को लाने का प्रयास कर रहा है।

नोएडा में डेढ़ साल देरी से लिंक रोड परियोजना

एलजी चौक से सेक्टर-145 तक बन रहा लिंक, 2019 में योगी ने किया था शिलान्यास

पर्यायनियर समाचार सेवा | नोएडा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को हिंडन नदी पर पुल के जरिए ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक से जोड़ने वाली ऑपनल सड़क अगले डेढ़ साल तक शुरू नहीं हो सकेगी। ये रोड 2 किमी से अधिक लंबी है।

ये एलजी चौक से सेक्टर 146-147 में 45 मीटर चौड़ी सड़क से शुरू होते हुए हिंडन नदी पर पुल से होते हुए नोलेज पार्क 3 एलजी चौक तक जाती है। इसका काफी हिस्सा भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर फंस रही है। इसके निपटारे के लिए यहां एंटीसी क्लोज लगाया जा सकता है। इसमें नोएडा और ग्रेटरनोएडा के एप्रोच रोड के हिस्सा है। जीएनआईडीए अधिकारियों के अनुसार, हिंडन नदी पर 290 मीटर लंबे पुल की निर्माण एजेंसी यूपीएसबीसीएन के हाल में परियोजना को पूरा करने के लिए 18 महीने के टाइम एक्सटेंशन मांगा था। इस दौरान दोनों ओर यानी नोएडा और ग्रेटरनोएडा की एप्रोच रोड बनाई जाएंगी। वर्तमान में हिंडन पुल पर निर्माण 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अप्रैल 2026 से पहले इसके



तैयार होने की संभावना नहीं है। पुल के लिए आवश्यक

16 फाउंडेशन और सब कंस्ट्रक्चर में से केवल चार का निर्माण हो सका है। बाकी भूमि अधिग्रहण में फंसा है। नोएडा प्राधिकरण की साइड से देखे तो जनवरी 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रोड का शिलान्यास किया था। इस योजना को डेढ़ साल में पूरा किया जाना था। हालांकि, नोएडा प्राधिकरण की ओर से भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण शिलान्यास के तुरंत बाद इसे रोक दिया गया था। 40 मीटर चौड़े हिंडन पुल का काम ढाई साल रुकने के बाद नवंबर 2023 में फिर से शुरू हुआ और इस साल दोनों प्राधिकरण द्वारा एप्रोच रोड का निर्माण शुरू किया गया है। एक बार पूरा होने पर यह मार्ग नोएडा से ग्रेटर नोएडा, जिला कलेक्ट्रेट, सूरजपुर और गाजियाबाद जाने वालों के लिए यात्रा को दूरी लगभग 16 किमी कम कर देगा।

18वीं मंजिल से कूदकर इंजीनियर की पत्नी ने दी जान

गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मंगलवार को इंजीनियर की पत्नी ने 18वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी।

नीति खंड चौकी क्षेत्र स्थित सर्वोत्तम सोसाइटी के नीचे उसकी लाश पड़ी मिली। ये सोसाइटी एकदम सुनसान इलाके में है। इंदिरापुरम थाना पुलिस को मंगलवार दोपहर सूचना मिली कि सर्वोत्तम सोसाइटी के नीचे एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस ने इस बिल्डिंग की तलाशी ली तो 18वीं मंजिल यानी छत पर एक मोबाइल पड़ा मिला। मोबाइल से महिला को पहचान स्प्लिट किया के रूप में हुई है। वो वसुंधरा सेक्टर-10 की रहने वाली थी।

ज्योति की शादी दिसंबर-2023 में नीतिश कुमार से हुई थी। नीतिश सीईएल में जूनियर इंजीनियर है। घटनास्थल पर मृतका का पति नीतिश पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया-दोनों के बीच पारिवारिक झगड़े चल रहे। सोमवार रात घर में लड़ाई होने के बाद पत्नी गुस्से में घर से निकल गई थी।

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all general public that my client Anita Dawar D/o Late Ram Narayan Dawar R/o C-336, GF, Vikas Puri, New Delhi-110018 has disowned and debarred her son Sahil Kumar from all her moveable & immovable properties and severed all relations. Anybody dealing with him in any manner whatsoever will be doing so at his/her own cost, risk & responsibilities. My client & her family members will not be responsible for any of his act.

ROHIT YADAV (Advocate)
Ch. 402 Civil Wings Tishazari, Delhi-50

गाजियाबाद में कस्तूरबा स्कूल से 3 छात्राएं लापता

पर्यायनियर समाचार सेवा | गाजियाबाद

गाजियाबाद में ब्लॉक रजापुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से सोमवार रात तीन छात्राएं लापता हो गईं।

इसमें एक छात्रा 7वीं और दो छात्राएं 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। सोमवार रात तीनों हॉस्टल में मौजूद थीं और अपने-अपने कमरों में सोई थीं। मंगलवार सुबह तीनों छात्राएं मिसिंग पाई गईं। जब हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो तीनों छात्राएं एकसाथ बैग लेकर जाती हुई दिखाई दी हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर है और छानबीन में जुटी हुई है। सिहानी गेट थाने के एसएचओ सचिन ने बताया-छात्राओं के नाम-पते दर्ज कर लिए गए हैं। उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें ढूढ़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है।

हॉस्टल के बाहर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। उधर, इस घटनाक्रम से कस्तूरबा स्कूल

हॉस्टल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रात के वक्त हॉस्टल और स्कूल के सभी गेट बंद रहते हैं। इसके बावजूद तीनों छात्राएं कैसे बाहर निकल गईं? इस पर भी पुलिस जांच कर रही है।

शहर के दो रूट पर ई-रिक्शा बंद करने पर हंगामा, लगाया जाम

पर्यायनियर समाचार सेवा | गाजियाबाद

गाजियाबाद में कई रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा का संचालन बंद कर दिया है। जिसको लेकर चौरफाा इसका विरोध शुरू हो गया है। सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों ने मंगलवार को शहर में कई स्थानों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ये फैसला मोदी-योगी की नीतियों के विरुद्ध बताया है। पुलिस

ट्रेड शो में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों की लगेगी प्रदर्शनी

नोएडा। यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में लोग इलेक्ट्रिक वाहन बुक करा सकेंगे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोस मार्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी हॉल संख्या 15ए में लगेगी। इसका आयोजन 25 से 29 सितंबर तक होगा। एशार्टीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पहले दो हजार वर्ग मीटर जगह निर्धारित की गई थी।

इसमें जल परिवहन, सड़क सुरक्षा, मॉडर्न फिटनेस केंद्र और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र प्रदर्शित किए जाएंगे। यह प्रदर्शनी हाल संख्या तीन में लगेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी हॉल संख्या 15ए में लगेगी। इसमें अभी तक 11 डीलर्स द्वारा 438 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित किया जा चुका है। कई अन्य डीलर्स ने भी प्रदर्शनी में हिस्सा लेने की सहमति दी है। बाकी हिस्सा भी जल्द ही आरक्षित हो जाएगा।



चोरी में मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही से चोरी किये हुए 50 हजार रूपये नगद व आभूषण को बरामद किए।

अस्पताल में नर्स से बदतमीजी, वार्ड बॉय को पीटा

गाजियाबाद। गाजियाबाद में मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल में लाए गए एक व्यक्ति ने मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी की। उसने स्टाफ नर्स को थपड़ मारने का प्रयास किया और वार्ड बॉय से मारपीट की। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कविनगर थाना पुलिस ने नेहरूनगर निवासी आशुतोष गर्ग को 8 सितंबर की रात सवा 10 बजे मेडिकल परीक्षण के लिए संजयनगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में भेजा। स्टाफ नर्स के अनुसार आशुतोष शराब के नशे में धुत था। उसने ब्लड सैंपल लेने के दौरान स्टाफ से अभद्रता करनी शुरू कर दी। मुझे थपड़ मारने का प्रयास किया, मैं पीछे हट गई। आरोपी ने वार्ड बॉय और राहुल के साथ मारपीट की। वहां मौजूद डॉक्टर और फार्मासिस्ट से भी गाली-गलौज की गई। इससे वार्ड में अत्यवस्था फैल गई। स्टाफ नर्स पूजा ने इस संबंध में थाना मधुवन बापूधाम में आरोपी आशुतोष गर्ग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-121, 132 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आशुतोष गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है।

साइबर अपराधियों ने खाते से निकाले 1.60 लाख

नोएडा। थाना बिसराख के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सुरेंद्र कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह दिल्ली में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार वह अपने बेटे को नोएडा में शिफ्ट करवाने के लिए आए थे। पीड़ित के अनुसार उन्होंने 29 जुलाई को एक एटीएम मशीन से कुछ पैसे बिड़्रा किया। इसके बाद अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके खाते से दो बार में 1,60,000 रुपए निकाल लिये। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले को जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिन एटीएम मशीनों से पैसे निकाले गए हैं, पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।

कारोबारी युवती पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार

गाजियाबाद। बीती रात कविनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरडीसी में स्थित एक होटल के सामने गाड़ी हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसके बाद एक पक्ष ने कारोबारी युवती व उसके दो भाईयों के साथ अभद्रता व धक्का-मुक्का और फायरिंग भी की थी। उक्त अपराधि घटना की सूचना मिलने के बाद कविनगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। उसके बाद पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आरोपित पक्ष के खिलाफ सुसंग धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करके मुख्य आरोपित सूरज चतुर्वेदी उर्फ सुर्ज चतुर्वेदी को हिरासत में ले लिया था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिये हैं। इस अपराधिक घटना के संदर्भ में एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि कविनगर पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

एयरपोर्ट प्रभावित किसानों के समर्थन में उतरी सापा

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित गांव रहनेवा एल सलारपुर अंडरपास पर लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सापा द्वारा प्रामोणों की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन यीडा सीईओ को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट से गांव रहनेवा के प्रभावित किसान पर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। वहीं दूनकौर क्षेत्र के गांव सलारपुर में 100 वर्ष पुराने मार्ग को बंद करने के विरोध में ग्रामीण काफी लंबे समय से धरना दे रहे हैं, लेकिन यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों व गामोणों की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक
सेक्टर 46-फरीदाबाद शाखा
(पता: एसीओएफ 63, सेक्टर-46 - फरीदाबाद, फरीदाबाद
फोन: 0129-2438938 और ईमेल: lob@1836@lob.in)

सांकेतिक कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर-46, फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिकृत (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर श्री/मैसर्स 1. मैसर्स ओएसएम प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (उधारकर्ता) 2. श्री लोकांश शर्मा (निदेशक) 3. श्री सुरेंद्र शर्मा (निदेशक/बंधककर्ता/गारंटर) 4. श्री दिनेश शर्मा (निदेशक/गारंटर) 5. श्री मुनेश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 6. श्रीमती पूनम शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 7. श्री अजय विक्रम सिंह (बंधककर्ता/गारंटर) 8. श्री सुरीश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 9. श्रीमती सुमन शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 10. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 11. श्री विपिन शाहिन्य (बंधककर्ता/गारंटर) 12. श्री रमेश चंद शर्मा (गारंटर)

(इसके बाद 'कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता' के रूप में संदर्भित) को मांग सूचना दिनांक 20-05-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 31,20,35,423.71 (रु. इकतीस करोड़ बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तेईस और पैंसे इक्कतर) दिनांक 17.05.2024 तक बैंक गारंटी सहित और सविदात्मक दर पर ब्याज, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण चुकोती की स्थिति तक, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

(1) कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने इसमें नीचे बर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को लिया है।

(2) विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन ओवरसीज बैंक, के प्रभार वाले रु. 31,91,53,920.06 (रु. इकतीस करोड़ इक्काने लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस और पैंसे छह) दिनांक 09.09.2024 तक अग्रपय बैंक गारंटी सहित और सविदात्मक दर पर ब्याज और अर्जित प्रभार, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा। जिसमें मांग नोटिस में उल्लिखित उपरोक्त तारीख से भुगतान की तारीख तक अनुबन्ध दर्ती और सहमति के अनुसार शेष राशि, शुल्क, लागत आदि पर ब्याज शामिल होगा, जिसमें मांग नोटिस जारी होने के बाद किए गए पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को घटाय जाएगा। दिनांक 09.09.2024 तक देय बकाया राशि रु. 31,91,53,920.06 (रु. इकतीस करोड़ इक्काने लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस और पैंसे छह) जिसमें भुगतान की स्थिति तक सविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और शेष, शुल्क आदि के साथ देय अग्रपय बैंक गारंटी शामिल है।

(3) कर्जदार का ध्यान एतद की धारा 13 की उप धारा (b), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रिहायशी प्लॉट नं. 550-ए, ओमकंस सिटी, सेक्टर 11-14, पलवल, यह सम्पत्ति श्री सुरेंद्र शर्मा व श्री रमेश चंद शर्मा के नाम पर है।
टाइटल डीड के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल - 264.25 वर्ग मी.
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट/प्लेट नं. 550-ए, सर्वे नं. 550-ए/रिटी या टीउन, सर्वे नं./खसरा नं. उध-जिला फरीदाबाद और जिला (हरियाणा) के अंतर्गत पंजीकृत, चौकी:
उत्तर में - प्लॉट नं. 549ए
दक्षिण में - प्लॉट नं. 551ए
पूर्व में - 12मी. चौड़ी रोड
पश्चिम में - अन्य की सम्पत्ति

दिनांक: 11.09.2024
स्थान: फरीदाबाद

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक
सेक्टर 46-फरीदाबाद शाखा
(पता: एसीओएफ 63, सेक्टर-46 - फरीदाबाद, फरीदाबाद
फोन: 0129-2438938 और ईमेल: lob@1836@lob.in)

सांकेतिक कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर-46, फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिकृत (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर श्री/मैसर्स 1. मैसर्स ओएसएम प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (उधारकर्ता) 2. श्री लोकांश शर्मा (निदेशक) 3. श्री सुरेंद्र शर्मा (निदेशक/बंधककर्ता/गारंटर) 4. श्री दिनेश शर्मा (निदेशक/गारंटर) 5. श्री मुनेश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 6. श्रीमती पूनम शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 7. श्री अजय विक्रम सिंह (बंधककर्ता/गारंटर) 8. श्री सुरीश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 9. श्रीमती सुमन शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 10. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 11. श्री विपिन शाहिन्य (बंधककर्ता/गारंटर) 12. श्री रमेश चंद शर्मा (गारंटर)

(इसके बाद 'कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता' के रूप में संदर्भित) को मांग सूचना दिनांक 20-05-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 31,20,35,423.71 (रु. इकतीस करोड़ बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तेईस और पैंसे इक्कतर) दिनांक 17.05.2024 तक बैंक गारंटी सहित और सविदात्मक दर पर ब्याज, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण चुकोती की स्थिति तक, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

(1) कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने इसमें नीचे बर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को लिया है।

(2) विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन ओवरसीज बैंक, के प्रभार वाले रु. 31,91,53,920.06 (रु. इकतीस करोड़ इक्काने लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस और पैंसे छह) दिनांक 09.09.2024 तक अग्रपय बैंक गारंटी सहित और सविदात्मक दर पर ब्याज और अर्जित प्रभार, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा। जिसमें मांग नोटिस में उल्लिखित उपरोक्त तारीख से भुगतान की तारीख तक अनुबन्ध दर्ती और सहमति के अनुसार शेष राशि, शुल्क, लागत आदि पर ब्याज शामिल होगा, जिसमें मांग नोटिस जारी होने के बाद किए गए पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को घटाय जाएगा। दिनांक 09.09.2024 तक देय बकाया राशि रु. 31,91,53,920.06 (रु. इकतीस करोड़ इक्काने लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस और पैंसे छह) जिसमें भुगतान की स्थिति तक सविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और शेष, शुल्क आदि के साथ देय अग्रपय बैंक गारंटी शामिल है।

(3) कर्जदार का ध्यान एतद की धारा 13 की उप धारा (b), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

औद्योगिक भूनि एवं भवन जोकि गैंग कोट, हमियन, पलवल, यह सम्पत्ति मैसर्स जी एस एम प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के नाम पर है।
टाइटल डीड के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल - 7 एकड़ 1 कनाल 1 मरला

संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट/प्लेट नं. सर्वे नं./रिटी या टीउन, सर्वे नं./खसरा नं. उध-जिला पलवल और जिला (हरियाणा) के अंतर्गत पंजीकृत, चौकी:
उत्तर में - खेतौहर भूमि
दक्षिण में - खेतौहर भूमि
पूर्व में - पीडब्ल्यूटी शक्तिन रोड
पश्चिम में - खेतौहर भूमि

दिनांक: 11.09.2024
स्थान: फरीदाबाद

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक
सेक्टर 46-फरीदाबाद शाखा
(पता: एसीओएफ 63, सेक्टर-46 - फरीदाबाद, फरीदाबाद
फोन: 0129-2438938 और ईमेल: lob@1836@lob.in)

सांकेतिक कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर-46, फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिकृत (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर श्री/मैसर्स 1. मैसर्स ओएसएम प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (उधारकर्ता) 2. श्री लोकांश शर्मा (निदेशक) 3. श्री सुरेंद्र शर्मा (निदेशक/बंधककर्ता/गारंटर) 4. श्री दिनेश शर्मा (निदेशक/गारंटर) 5. श्री मुनेश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 6. श्रीमती पूनम शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 7. श्री अजय विक्रम सिंह (बंधककर्ता/गारंटर) 8. श्री सुरीश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 9. श्रीमती सुमन शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 10. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 11. श्री विपिन शाहिन्य (बंधककर्ता/गारंटर) 12. श्री रमेश चंद शर्मा (गारंटर)

(इसके बाद 'कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता' के रूप में संदर्भित) को मांग सूचना दिनांक 20-05-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 31,20,35,423.71 (रु. इकतीस करोड़ बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तेईस और पैंसे इक्कतर) दिनांक 17.05.2024 तक बैंक गारंटी सहित और सविदात्मक दर पर ब्याज, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण चुकोती की स्थिति तक, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

(1) कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने इसमें नीचे बर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को लिया है।

(2) विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन ओवरसीज बैंक, के प्रभार वाले रु. 31,91,53,920.06 (रु. इकतीस करोड़ इक्काने लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस और पैंसे छह) दिनांक 09.09.2024 तक अग्रपय बैंक गारंटी सहित और सविदात्मक दर पर ब्याज और अर्जित प्रभार, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा। जिसमें मांग नोटिस में उल्लिखित उपरोक्त तारीख से भुगतान की तारीख तक अनुबन्ध दर्ती और सहमति के अनुसार शेष राशि, शुल्क, लागत आदि पर ब्याज शामिल होगा, जिसमें मांग नोटिस जारी होने के बाद किए गए पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को घटाय जाएगा। दिनांक 09.09.2024 तक देय बकाया राशि रु. 31,91,53,920.06 (रु. इकतीस करोड़ इक्काने लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस और पैंसे छह) जिसमें भुगतान की स्थिति तक सविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और शेष, शुल्क आदि के साथ देय अग्रपय बैंक गारंटी शामिल है।

(3) कर्जदार का ध्यान एतद की धारा 13 की उप धारा (b), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रिहायशी सम्पत्ति - प्लॉट नं. 1008, अरबन इंस्टेट सेक्टर-2, पलवल, यह सम्पत्ति श्री मुनेश शर्मा श्री योगेश्वर शर्मा और श्रीमती पूनम शर्मा पत्नी श्री मुनेश शर्मा के नाम पर है।
टाइटल डीड के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल - 84 वर्ग मी.

संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं./प्लेट नं. 1008, सर्वे नं. 1008/रिटी या टीउन, सर्वे नं./खसरा नं. उध-जिला पलवल और जिला (हरियाणा) के अंतर्गत पंजीकृत, चौकी:
उत्तर में - प्लॉट नं. 1007A (पंचाल निगर) 1007B
दक्षिण में - प्लॉट नं. 1009
पूर्व में - अन्य की सम्पत्ति
पश्चिम में - रोड और टीगोर पब्लिक स्कूल

दिनांक: 11.09.2024
स्थान: फरीदाबाद

ह

आप सरकार को गिराने की साजिश : आतिशी

● मंत्री का आरोप, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की चल रही तैयारी

● भाजपा के ज्ञापन पर एक दिन पहले राष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय के पास उचित ध्यान के लिए मेजा था

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को पिछले दरवाजे से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि, भाजपा चार दरवाजे से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि, भाजपा का एक मात्र काम चुनी हुई विपक्षी सरकारों को गिराना है।

यह आरोप ऐसे समय लगाया गया है, जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय ने विपक्षी दल भाजपा के एक ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास उचित ध्यान के लिए भेज दिया था। ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है। आतिशी ने कहा कि, भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं खरीद सकी इसलिए अब दिल्ली की चुनी हुई



सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दिया है। आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार को गिराया गया तो दिल्लीवासी आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को शून्य सीट देकर कराया जावे और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आप नीत सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। आतिशी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम देश में निर्वाचित सरकारों को अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए गिराना है, जैसा कि महागठ, कर्नाटक और मणिपुर में हुआ।

मंत्री ने आरोप लगाया, उन्होंने आप विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने के लिए दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस की कोशिश की,

भाजपा को आज हारना है या चार माह बाद : संजय सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की हार तय है। अब भाजपा को यह तय करना है कि उसे दिल्ली में आज हारना है या फिर चार माह बाद हारना है। उन्होंने कहा, अगर भाजपा वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी हारना चाहते हैं तो अभी चुनाव की घोषणा कर दें। आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हट रही है।

लेकिन वे असफल रहे। अब वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रिय सरकार को गिराने के लिए पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे हैं।

विक्टिम कार्ड खेलकर मुद्दे से भटकाना बंद करे: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनके द्वारा राष्ट्रपति को 30 अगस्त को दिए गए ज्ञापन में उठाये गए मुद्दों पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं होने, दिल्ली की पंगु हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था, केग की 11 रिपोर्ट्स को सदन में न रखने और केंद्र सरकार की योजनाओं को जानबूझकर राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं करने के मुद्दों को उठाया था, जिनका जवाब केजरीवाल सरकार को देना है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं कर संविधान का उल्लंघन किया है। जिसके चलते दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति अत्यवस्थित हो चुकी है। आप सरकार ने पिछले 5 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया है। जबकि नियमानुसार पिछले सत्र के बाद 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना अनिवार्य है। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहां की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अराजकता का माहौल है। आप विक्टिम कार्ड खेलकर मुद्दों से दिल्ली की जनता को भटका रही है।

एलएनजेपी अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीज की हालत स्थिर : भारद्वाज

● स्वास्थ्य मंत्री ने डेगू से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए अस्पताल का औचक निरीक्षण किया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीज की हालत स्थिर है। भारद्वाज ने मंकी पॉक्स और डेगू से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, एलएनजेपी अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक मरीज है। उसका यात्रा इतिहास है और ऐसा माना जा रहा है कि वह विदेश यात्रा के दौरान संक्रमित हुआ। मरीज को अलग वार्ड में रखा गया है, उसकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के हिसार निवासी 26 वर्षीय मरीज को केवल जनानों में छाले और त्वचा पर चकते हैं, लेकिन



एलएनजेपी में भर्ती मंकी पॉक्स के मरीज का हालचाल जानने पहुंचे सौरभ।

बुखार नहीं है। भारद्वाज ने कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर चर्चाओं की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हवा से नहीं बल्कि संपर्क से फैलता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह एक अकेला मामला है और इससे लोगों को तत्काल कोई खतरा नहीं है। मंत्रालय ने कहा, यह व्यक्ति, एक युवा पुरुष है जो हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमण प्रभावित देश से यात्रा करके लौटा है, उसे वर्तमान में एक निर्दिष्ट देखभाल पृथकवास इकाई में रखा गया है। चिकित्सकीय रूप से रोगी की हालत स्थिर बनी हुई है और उसे कोई भी अन्य बीमारी नहीं है। मरीज को शनिवार को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विश्व स्वास्थ्य

संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले महीने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसकी व्यापकता और प्रसार को देखते हुए दूसरी बार मंकी पॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। एलएनजेपी को नोडल सुविधा के रूप में नामित किया गया है, जबकि स्थिति को देखते हुए दो अन्य अस्पतालों को भी तैयार रखा गया है। एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के लिए कुल 20 आइसोलेशन कमरे हैं, जिनमें से 10 कमरे पुट मामलों के लिए आरक्षित किए गए हैं। गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल और बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए 10-10 कमरे होंगे, जबकि संदिग्ध मामलों के लिए पांच-पांच कमरे आरक्षित रहेंगे।

हाईकोर्ट ने दी मद्रास कैप निवासियों का राहत

● प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं करने दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुराने बारापुला ब्रिज क्षेत्र में मद्रासी कैप के निवासियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। नए फ्लाइंगोवर के निर्माण को लेकर इन लोगों को उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने इस नोटिस के खिलाफ जंगपुरा के जेजे क्लस्टर मद्रासी कैप के निवासियों द्वारा दायर की गई अर्जी पर दिल्ली सरकार, उसके लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि कॉलोनी जल प्रवाह में बाधा डाल रही है या नहीं। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि यह जल प्रवाह में बाधा डाल रही है तो इसे हटाना ही



होगा। उच्च न्यायालय ने कहा, यदि यह जलप्रवाह में बाधा डाल रही है तो इसे हटाना ही होगा। शहर में अनावश्यक ही पानी भर जा रहा है। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं और कर दे रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनके घरों में पानी भर जाए। हम शहर में बार-बार पानी नहीं भरने दे सकते। यदि नाले को साफ करना है, तो उसे साफ करना ही होगा।

पीठ ने कहा, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको वैकल्पिक जमीन पर ले जाया जाए। हम प्रशासन से आपका पुनर्वास कराने को कहेंगे। हम आपको पुनर्वास का अधिकार देंगे। उच्च न्यायालय ने प्रशासन को 10 दिनों के अंदर इस बात पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि कॉलोनी जलप्रवाह में बाधा डाल रही है या नहीं। डीडीए की वकील प्रभाशाय कौर ने कहा कि यह कॉलोनी जलप्रवाह में बाधा डाल रही है और लोक निर्माण विभाग अदालत को पूरा विवरण दे सकता है।

एक भी झुग्गी टूटने नहीं देगी सरकार: सिसोदिया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि मद्रासी कैप की एक भी झुग्गी को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार नहीं गिरने देगी।

मनीष सिसोदिया ने यह दावा मद्रासी कैप के पीड़ित परिवारों से अपने दौरे के दौरान किया। मनीष सिसोदिया ने पुराना बारापुला के पास बसी मद्रासी कैप में रह रहे लोगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया, जिन्हें एलजी द्वारा सैकड़ों झुग्गियों तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की 'आप' सरकार उनके साथ खड़ी है। दिल्ली में जब तक 'आप' की सरकार है, तब तक किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अपने एलजी से कहकर अस्थायी को उधारी-धमकाती है और फिर नोटिस दिलाती है।

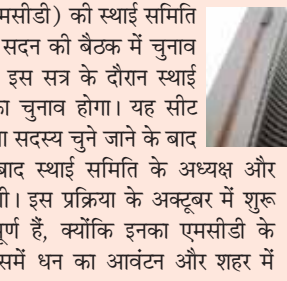
गलत बयानबाजी कर रहे मनीष : विवेक सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पिछले दस साल में केजरीवाल सरकार ने झुग्गी क्लस्टरों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित रखा ही है, उनकी सरकार के ड्यूटिस विभाग ने उनके पुनर्वास के लिए बिल्कुल काम नहीं किया है। अनेक झुग्गी बस्तियों की तरह ही जंगपुरा विधानसभा की मद्रासी बस्ती का भी है जिसका मामला न्यायलय में था पर दिल्ली सरकार ने और ना उसके ड्यूटिस विभाग ने इस बस्ती को बचाने के लिए और ना ही इनके पुनर्वास के लिए कोई प्रस्ताव न्यायलय के समक्ष रखा। सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने उक्त मद्रासी बस्ती के लोगों को झुग्गी खाली करने का नोटिस दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कालका जी, जेलर बाग एवं कपूरली कॉलोनी के झुग्गी वासियों के पुनर्वास का काम चलाया है, सिसोदिया एक झुग्गी क्लस्टर बताते जहां दस साल में सरकार ने झुग्गीवासियों के जीवन सुधार का काम किया हो।

एमसीडी स्थाई समिति का चुनाव 26 सितंबर को होगा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थाई समिति के चुनाव 26 सितंबर को होंगे। एमसीडी सदन की बैठक में चुनाव होंगे, जो उसी दिन आहूत की जाएगी। इस सत्र के दौरान स्थाई समिति में रिक्त एक सीट पर सदस्य का चुनाव होगा। यह सीट भाजपा पार्षद कमल सहरावत के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई है। रिक्त पद भरे जाने के बाद स्थाई समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है।

यह पद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका एमसीडी के कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जिसमें धन का आवंटन और शहर में



विकास परियोजनाओं को देखेरूक शामिल है 18 सदस्यीय स्थाई समिति में भाजपा ने हाल ही में हुए वार्ड समिति के चुनाव में सात सीटें हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत की है। वार्ड समितियों से 12 सदस्य स्थाई समिति में शामिल होंगे, जिनमें से सात भाजपा पार्षद होंगे। शेष छह सीटों में से तीन भाजपा और तीन आम आदमी पार्टी के पास हैं जो उन्होंने 2022 में हुए स्थाई समिति के पिछले चुनाव में हासिल की थी। इनमें से एक सीट कमलजीत सहरावत के इस्तीफे से खाली हुई है, जिसे भरने के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।

देवेन्द्र यादव ने ली 14 जिला कांग्रेस कमेटीयों की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में सभी 14 जिला कांग्रेस कमेटीयों में संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, संगठनात्मक मजबूती और केन्द्र और दिल्ली सरकारों की गलत नीतियों से परेशान दिल्लीवालों की लड़ाई लड़ने आदि की चर्चा के संबंध में मासिक बैठक हुई। बैठक में देवेन्द्र ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लगातार संघर्ष के बाद दिल्ली में जो माहौल बना रहा है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिल्ली में बदलाव लाने के लिए भरपूर उत्साह और जोश पनप रहा है। जिला बैठकों में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, निगम पार्षद मौजूद रहे।

नए आपराधिक कानूनों की एलजी ने की समीक्षा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में एलजी ने इस दिशा में किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में तेजी लाने को कहा। बैठक में एलजी ने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव से सभी संबंधित विभागों की एक कमेटी गठित करने को कहा, ताकि स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जैसे- भर्ती नियमों को अंतिम रूप देना, पदों का विज्ञापन आदि को एक ही बार में पूरा कर, नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई

● मुख्य सचिव से नियुक्तियों में तेजी लाने व संबंधित विभागों की एक समिति गठित करने के लिए निर्देश

जा सके। भर्ती मामले में शामिल विभागों में सेवा, प्रशासनिक सुधार, वित्त और उपयोगकर्ता विभागजैसे- सख्त अभियोजन निदेशालय और जेल शामिल हैं। इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव के अलावा, गृह विभाग, दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लैब, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, अभियोजन निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्त

और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख मौजूद रहे। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक दौर के बने कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इस मुद्दे पर उपराज्यपाल की यह चौथी समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में कई विषयों पर विचार व्यक्त किया गया, जिसमें मेंडिको लीगल के लिए स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा तैयार नोडल अधिकारी की ट्रेनिंग और विभिन्न कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों में भर्तियां शामिल हैं।

सात छात्रों को सेंट स्टीफंस कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन सात छात्रों को सेंट स्टीफंस कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दे दी, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों के आधार पर कॉलेज (सेंट स्टीफंस) में प्रवेश की मांग करती हुए अदालत का दरवाजा खटखटया था।

हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह सीटों का कोई और आवंटन न करे। खंडपीठ ने कॉलेज की अपील पर



विश्वविद्यालय और सात छात्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कॉलेज ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों के आधार पर इन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया है। अदालत ने उनसे (विश्वविद्यालय और छात्रों) चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने

● हाईकोर्ट की पीठ ने अदालत आने वाले छात्रों को दी राहत

को कहा और मामले की अगली सुनवाई अगले साल 28 जनवरी को तय की। पीठ ने कहा, अदालत का दरवाजा खटखटयने वाले सात छात्रों को अगले आदेश तक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। हालांकि यह निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय आगे सीटों का कोई आवंटन नहीं करेगा। छह सितंबर को एकल न्यायाधीश ने सात छात्रों को राहत देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं थी क्योंकि संस्थान एवं विश्वविद्यालय के बीच जारी विवाद के कारण उन्हें अनुचित परेशानी का सामना करना पड़ा।

मेट्रो में इस साल चार हजार चोरी के मामले

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 242 मामलों की वृद्धि के साथ इस वर्ष अब तक 3,952 चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल आठ सितंबर तक दिल्ली मेट्रो में चोरी के कम से कम 3,709 मामले दर्ज किए गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चोरी के इन मामलों में यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों की जेब काटना, मोबाइल फोन, पर्स या अन्य कीमती सामान गायब होना शामिल है। मेट्रो संपत्तियों की चोरी भी इन्हीं आंकड़ों में दर्ज है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 3,952 मामलों में चोरी के कम से कम 3,898 मामले ई-प्राथमिकी के माध्यम से दर्ज किए गए और उनमें से 548 मामलों को इस साल आठ सितंबर तक सुलझा लिया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में इसी अवधि में 3,709 प्रकरणों में से चोरी के कम से कम 3,648 मामले ई-प्राथमिकी के माध्यम से दर्ज किए गए और उनमें से 1,471 मामलों को हल कर लिया

● पिछले वर्ष की तुलना में वारदात में हुई बढ़ोतरी

गया। आंकड़ों के अनुसार इस साल आठ सितंबर तक दिल्ली मेट्रो परिसर से मोटर वाहन चोरी के कम से कम 81 मामले हैं और पिछले साल इसी अवधि में 72 मामले दर्ज किए गए। इस साल आठ सितंबर तक 2024 में कम से कम 56 और 2023 में 61 मामले सुलझाए जा चुके हैं। इस साल आठ सितंबर तक कम से कम 11 संधमारी के मामले सामने आए हैं। जबकि 2023 में दिल्ली मेट्रो के परिसर में संधमारी के सिर्फ तीन मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार इस साल आठ सितंबर तक लूट के कम से कम तीन मामले दर्ज किए गए और उनमें से दो को सुलझा लिया गया है। पिछले साल इसी अवधि में लूट के दो मामले दर्ज किए गए थे और दोनों को सुलझा लिया गया था। पिछले वर्ष आठ सितंबर तक डकैती के कम से कम पांच मामले दर्ज किए गए।

चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या बढ़ाने की योजना

नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर चार प्रजातियों के पशुओं के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उनकी दिनचर्या व आहार पर बारीकी से निगरानी के साथ-साथ हार्मोनल रेगुलेशन जैसे उपायों को लागू कर रहा है। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कई जानवरों के हाल के वर्षों में बच्चे पैदा नहीं हुए, जिसके कारण इस मुद्दे के समाधान के लिए टोस प्रयास किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया, हम वर्तमान में चिड़ियाघर में चार प्रजातियों की निगरानी कर रहे हैं जो या तो प्रजनन नहीं कर रही हैं या अब प्रजनन करने में सक्षम नहीं हैं। इन प्रजातियों में भारतीय जंगली कुत्ता, शेर, भेड़िया और बबून शामिल हैं। चिड़ियाघर के अधिकारी ने कहा, हम उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

मादीपुर वार्ड में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

नई दिल्ली। मेयर डॉ शैली ओबेरॉय ने पश्चिमी ज़ोन के मादीपुर वार्ड में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, मेयर ने मादीपुर वार्ड के कई ढलाव घरो का दौरा किया और पाया कि ढलाव घरो के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और मुख्य सड़कों तक है जिस कारण क्षेत्र में गंदगी और बदबू है और नागरिक भी लगातार शिकायत कर रहे हैं। मेयर ने कूड़ा प्रबंधन प्राइवेट एजेंसी व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ढलाव घरो की मरम्मत कराई जाए और नियमित रूप से कूड़ा उठाया जाए। निरीक्षण के दौरान, मेयर ने पाया कि वार्ड में एक ढलाव घर के पास सड़क तक कूड़ा फैला हुआ है और स्थिति इतनी खराब है कि कूड़े व गंदगी के कारण नागरिकों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। नागरिकों ने बताया कि ढलाव घर के आस पास रिसावशी इलाका है और आग्रह किया कि इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाए।



● जीवन की कठिनाइयों का हल आत्महत्या नहीं नई दिल्ली। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर मंगलवार को रोहिणी में परफेक्ट हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आत्महत्या की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मनोचिकित्सक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी डॉ. आरपी पाराशर पाराशर ने कहा कि जीवन की कठिनाइयों का हल आत्महत्या नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है, जो केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा, आत्महत्या के पीछे विभिन्न कारण मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत चुनौतियां शामिल हैं। परफेक्ट हेल्थ इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशिका शिमोना ने कहा कि शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण जैसी घटनाओं के कारण मानसिक स्वास्थ्य को गहरे रूप से प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन इसका समाधान आत्महत्या कभी भी नहीं हो सकता है।

एमसीडी चलाएगी व्यापक स्वच्छता अभियान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024) तक वार्ड स्तर पर व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरणीय जम्मेदारियों को बढ़ावा देना है, जो शहर के विशिष्ट ज़ोन में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कचरा प्रबंधन और कूड़े के सही निपटान पर जोर दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा के दौरान, निगम मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगा, जिसमें गंदे स्थलों को सफाई और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसे कुल 74 स्पॉट्स (जीवीपी) को पहचान की गई है।

चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या बढ़ाने की योजना

नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर चार प्रजातियों के पशुओं के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उनकी दिनचर्या व आहार पर बारीकी से निगरानी के साथ-साथ हार्मोनल रेगुलेशन जैसे उपायों को लागू कर रहा है। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कई जानवरों के हाल के वर्षों में बच्चे पैदा नहीं हुए, जिसके कारण इस मुद्दे के समाधान के लिए टोस प्रयास किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया, हम वर्तमान में चिड़ियाघर में चार प्रजातियों की निगरानी कर रहे हैं जो या तो प्रजनन नहीं कर रही हैं या अब प्रजनन करने में सक्षम नहीं हैं। इन प्रजातियों में भारतीय जंगली कुत्ता, शेर, भेड़िया और बबून शामिल हैं। चिड़ियाघर के अधिकारी ने कहा, हम उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

स्वास्थ्य: एम्स में होगा तंबाकू की लत छुड़ाने का इलाज

● अस्पताल में विशेष ओपीडी शुरू, मरीज सीधे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

तंबाकू की लत से परेशान लोगों और उनके परिवारों के लिए दिल्ली एम्स की तरफ से एक अच्छी खबर है। एम्स ने तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए 'तंबाकू सेवन उपचार क्लिनिक' की विशेष ओपीडी शुरू की है। यहां इलाज के इच्छुक मरीज सीधे यहां आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरे देश भर में तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ज्ञात



तंबाकू सेवन उपचार क्लिनिक' की विशेष ओपीडी शुरू करते एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास।

रहे कि तंबाकू के सेवन से हर साल दुनिया में करीब 80 लाख और भारत में 13 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एम्स के राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में तंबाकू सेवन

उपचार क्लिनिक की शुरुआत मंगलवार को की गई। क्लिनिक का उद्घाटन एम्स अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने किया। तंबाकू और धूम्रपान की लत से जुड़ा

क्लिनिक को एम्स अस्पताल के राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी की पांचवीं मंजिल ए विंग में पलमोनरी मेडिसिन विभाग के कमरा नंबर 519 और 526 में चालू किया

सीओपीडी और कैंसर का कारण है तंबाकू

एम्स दिल्ली के पलमोनरी, क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. अनंत मोहन ने बताया कि तंबाकू का उपयोग सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। क्लिनिक सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएगा और आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा अस्पताल में मरीज पंजीकरण के माध्यम से इलाज करा सकेंगे।

सीओपीडी और कैंसर का कारण है तंबाकू

एम्स दिल्ली के पलमोनरी, क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. अनंत मोहन ने बताया कि तंबाकू का उपयोग सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। क्लिनिक सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएगा और आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा अस्पताल में मरीज पंजीकरण के माध्यम से इलाज करा सकेंगे।

सीओपीडी और कैंसर का कारण है तंबाकू

एम्स दिल्ली के पलमोनरी, क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. अनंत मोहन ने बताया कि तंबाकू का उपयोग सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। क्लिनिक सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएगा और आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा अस्पताल में मरीज पंजीकरण के माध्यम से इलाज करा सकेंगे।

उदयभान के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब

● हुड़्डा भी रहे मौजूद, कहा- होडल के आशीर्वाद और उदयभान के नेतृत्व में जीतेगी कांग्रेस

● कांग्रेस की मंजूरशुदा परियोजनाएं भी पूरा नहीं कर पाईं भाजपा सरकार: पार्टी प्रदेशाध्यक्ष



कांग्रेस प्रत्याशी चौ. उदयभान का नामांकन कराने के दौरान मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड़्डा व अन्य नेता।

नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। कांग्रेस सरकार में होडल को बड़ी हिस्सेदारी मिलने जा रही है। इसलिए मतदाताओं से अपील है कि चौधरी उदयभान को सबसे ज्यादा मतों से जितकर विधानसभा में भेजें। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौ. करण सिंह दलाल, रघुवीर सिंह तेवतिया, चौ. लहरी सिंह के साथ-साथ 43 में से 41 गांवों के सरपंच, हसनपुर व होडल ब्लॉक समिति चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य और

होडल नगर पालिका के 16 सदस्य भी प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में चौ. उदयभान के समर्थन का ऐलान किया। हुड़्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने अपने 10 साल के राज में एक भी काम नहीं करवाया। भाजपा ने न तो एक नई यूनिट बिजली उत्पादन की लगवाई, न एक खंभा मेट्रो का लगाया, न ही कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला और न ही कोई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर का बड़ा

संस्थान, उद्योग या परियोजना लगाई। 2014 और 2019 में बीजेपी ने जो वादे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बजाए सरकार ने किसानों की लागत को कई गुना बढ़ा दिया। युवाओं को रोजगार देने की बजाए, हरियाणा को देश का सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया। महिलाओं, व्यापारियों को सुरक्षा देने की बजाए देश का सबसे असुरक्षित राज्य बना दिया।

‘जन आशीर्वाद से फिर बनेगी भाजपा सरकार’

● भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा की नामांकन समा में पहुंचे बिलाख देब व कृष्णापाल

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद



जीताकर विधानसभा में भेजना है। इस मौके पर उन्होंने राव दान सिंह को भी धेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दाग चुनाव हरियाणा के गौरव और स्वाभिमान को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस पर गरजते हुए बिलख देब ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों, जवानों को नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में जेल में बैठे सुरेंद्र पंवार जैसे व्यक्ति को टिकट दी है। कांग्रेस की सोच भ्रष्टाचारियों को चुनाव

पीठासीन अधिकारियों का किया गया रैंडमाइजेशन

गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन द्वारा पारदर्शिता बरती जा रही है। इसी को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी और वैकल्पिक पीठासीन अधिकारियों का प्रथम चरण का रैंडमाइजेशन किया गया। एनआईसी से डीआईओ विभू कपूर ने रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की। निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित किए गए एक सॉफ्टवेयर के जरिये कंप्यूटर में एक पीओ व एपीओ की कुल संख्या के क्रम को, अक्रमित कर पॉलिग पार्टियों की नई सूची तैयार की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पॉलिग पार्टियों की रैंडमाइजेशन तीन चरणों में पूरी की जाएगी।

गुरुग्राम, बादशाहपुर व सोहना से प्रत्याशियों ने किए नामांकन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन के छठे दिन जिले की पटौदी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य तीनों विधानसभा क्षेत्रों गुडगांव से दो, बादशाहपुर व सोहना से एक-एक प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।

विधानसभा चुनाव को नामांकन प्रक्रिया के तहत मंगलवार को जिला में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से मुकेश शर्मा व निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से राव नरबीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त सोहना विधानसभा क्षेत्र से भी निर्दलीय उम्मीदवार सुंदर भड़ाना ने अपना पत्रा भरा है। पटौदी विधानसभा से मंगलवार को भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है।

डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन शुल्क (सिक्योरिटी



बादशाहपुर सीट से नामांकन दाखिल करते भाजपा प्रत्याशी राव नरबीर सिंह।

रशि) के रूप में 10 हजार रुपये अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 5 हजार रुपये नामांकन शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। नामांकन भरने की अन्तिम तिथि 12 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक है। 13 सितम्बर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि 16 सितम्बर सोमवार को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे तथा इसी दिन बाद दोपहर चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की सूची चुनाव चिन्ह सहित जारी कर दी जाएगी।

नयनपाल रावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन

फरीदाबाद। पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नयनपाल रावत ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय



पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व चंदावली स्थित अपने कार्यालय पर पूजा अर्चना की और उपरिस्थ क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लिया। शशिबाला तेवतिया एवं उनकी बेटी ने तिलक लगाकर जीत का आशीर्वाद दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व चंदावली स्थित अपने कार्यालय पर उमड़े भारी जनसमूह को सम्बोधित करते हुए नयनपाल रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी है, जो लोगों का शोषण करते हुए आया है।

नयनपाल रावत ने कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी मेरे साथ हैं और मैं आपसे वादा करता हूं बिरादरी का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। टेकचंद शर्मा अपनी बिरादरी के भी सगे नहीं हूँ और इन्होंने आपसे मत लड़ाने का काम किया। ब्राह्मण समाज से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने नहीं सीखा है, उससे ज्यादा लोग ब्राह्मण समाज के मेरे साथ हैं। आज पृथला विधानसभा क्षेत्र की सरदारी यहाँ पहुँची है और सरदारी का सरकार में साझा होता है। आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से आपका बेटा आपका सेवादर पुनः एक बार ना केवल विधायक बल्कि हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर आयेगा।

आशीर्वाद बैठक में व्यापारियों ने दिया नवीन को समर्थन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

हरियाणा के व्यापारियों के सुख-दुख में सदा खड़े रहे नवीन गोयल के समर्थन में गुडगांव के व्यापारियों ने खुलकर समर्थन दे दिया है। यहां कोरस बैंक हॉल में हुई व्यापारी आशीर्वाद बैठक में गुडगांव के व्यापारियों, दुकानदारों की सभी एनॉसिएशन ने एक मंच पर आकर नवीन गोयल को विजयी बनाने की बात कही। व्यापार जगत के मजबूत स्तंभ इस बैठक में पहुंचे और नवीन गोयल को आशीर्वाद दिया। नवीन गोयल ने व्यापारियों का आशीर्वाद मिला है, वे इस आशीर्वाद से चुनाव की नैया पार कर जाएंगे। नवीन गोयल ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई देशों में घूमकर आईडिया इकट्ठे किए हैं। उनकी पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। व्यापार का सरलिकरण, व्यापारी के टेक्स का



व्यापारी आशीर्वाद बैठक को संबोधित करते नवीन गोयल।

देश के व्यापारी के मजबूत होने से यहां का विकास होता है। व्यापारी जिधर चलता है, उधर की हवा बनती है। व्यापारियों का उन्हें आशीर्वाद मिला है, वे इस आशीर्वाद से चुनाव की नैया पार कर जाएंगे। नवीन गोयल ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई देशों में घूमकर आईडिया इकट्ठे किए हैं। उनकी पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। व्यापार का सरलिकरण, व्यापारी के टेक्स का

व्यापारी वर्ग की एकजुटता से मिली ताकत: डॉ. गोयल

डा. डीपी गोयल ने गुरुग्राम के व्यापारियों, दुकानदारों से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि समाज को दिशा देने वाले, आप सब गुरुग्राम को चलाने वाले हैं। आपके यहां एकजुट होने से नवीन को ताकत मिली है। गुडगांव को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सेवा में 22 साल दिए हैं। हमारी नीयत में ना कोई खोट था, ना है और ना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा से नाता तोड़ते हुए दुख हमें था। क्योंकि हमने तोड़ना नहीं सीखा। हमने पार्टी का धर्म भी निभाया है।

बैठक में रामनिवास मंगला, जेएन मंगला, रोशन लाल मंगला, देवेंद्र जैन, दिनेश अग्रवाल, अरुण, नरेश गोयल, रवि समेत सभी वक्ताओं ने नवीन गोयल का खुलकर समर्थन करते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी

स्वास्थ्य जांच के साथ मतदान के लिए किया जागरूक

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

7वें पोषण माह के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा मंगलवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद में आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. नितिका शर्मा ने 218 मरीजों को बदलते मौसम में खान-पान के विषय में जानकारी दी व जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वीप प्रोग्राम के तहत लोगों को 100 प्रतिशत मतदान के लिए जागरूक किया।



आयुष विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे शिविर में जांच कराती छात्राएं।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ लोकतंत्र की रक्षा एक चिकित्सक का मौलिक कर्तव्य है। डॉ. नितिका ने कहा कि जिस तरीके से हम अपने खानपान के तरीके को सुधार कर खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मतदान

प्रक्रिया में भाग लेकर हम अपने देश के लोकतंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वस्थ शरीर व स्वस्थ लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में हम सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगामी 5 अक्टूबर को अपना वोट

डालने के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है। शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीतू कटारिया के द्वारा आयुर्वेदिक व डॉ. नितिका शर्मा ने होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों का परीक्षण किया एवं इलाज दिया गया।

दिव्यांगों ने ट्राई साइकिल से रैली निकाल दिया मतदान का संदेश

● एडीसी ने रैली को विकास सदन परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिले में स्वीप अभियान के तहत लगातार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में मंगलवार को स्वीप व जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में विकास सदन

परिसर से एडीसी एवं स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हितेश कुमार मीणा ने दिव्यांग मतदाताओं की ट्राई साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल दिव्यांग मतदाताओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए शत-प्रतिशत मतदान, गुरुग्राम का अभियान स्लोगन के नारे लगाए। ट्राई साइकिल रैली सदर बाजार होते हुए सेक्टर-15 स्थित जिला रेडक्रॉस कार्यालय में समाप्त हुई। इस दौरान एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि जिला में आगामी 5 अक्टूबर को कोई भी मतदाता मतदान से अछूता ना रहे। इसके लिए स्वीप अभियान के तहत निरन्तर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार



नेत्रदान पखवाड़ा के तहत आंखें दान करने की शपथ लेते लोग।

स्वास्थ्य विभाग ने मनाया नेत्रदान पखवाड़ा
गुरुग्राम। आंखें शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। नेत्रदान कर हम किसी दृष्टिहीन के जीवन में रोशनी ला सकते, यह हमारे जीवन के बाद की सबसे बड़ी नियामत होगी। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के दौरान नेत्ररोग विशेषज्ञा एवं डिप्टी सीएमओ डा. प्रिया शर्मा ने सेक्टर-31 के पॉलीक्लीनिक में स्वास्थ्य कर्मियों को नेत्रदान का संकल्प कराते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद भी हमारा शरीर चिकित्सा परीक्षण और नेत्रदान के काम आ सकता है। आज बहुत से ऐसे नागरिक हैं, जिन्होंने देहदान और नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के दौरान अनेक स्कूली विद्यार्थियों तथा नागरिकों ने फार्म भरकर आंखें दान करने का संकल्प लिया है। डिप्टी सीएमओ डा. प्रिया शर्मा ने बताया कि कार्या ना हो जाने के बाद प्रत्यारोपण से ही व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। जो कि मृतक की आंखों से मिलता है। इसका कोई और विकल्प नहीं है। इसी उद्देश्य से नेत्रदान का अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए गुरुग्राम के सैक्टर 31 स्थित पॉलीक्लीनिक से संपर्क किया जा सकता है अथवा टोल फ्री नंबर-112 को डायल किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि विधानसभा चुनाव के दौरान सभी कर्मचारी पांच अक्टूबर को अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए अवश्य जाएं।

विस चुनाव: आप ने जारी की नौ प्रत्याशियों की दूसरी सूची

● भाजपा छोड़कर आए पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह को बरवाला से बनाया प्रत्याशी

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह को बरवाला से उम्मीदवार बनाया गया है। सिंह एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से आप में शामिल हुए थे। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत विफल रहने के बाद सोमवार को पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी।

व्हाट्सएप कॉल कर लोगों के खातों से रुपए ठगने वाले को दबोचा

पलवल। फर्जी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर लोगों के खातों से रुपए ठगने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस ने मामले में करवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। साइबर थाना पुलिस इंचार्ज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली की लोगों के पास फर्जी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर लोगों के खातों से रुपए ठगने वाला एक आरोपी पलवल के आगरा चौक पर मौजूद है और बैंक से रुपए निकलने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो एक लड़का पुलिस को दिखाई दिया जिसने अपने पास एक काले रंग का बैग रखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत उक्त युवक को पकड़।

डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने पर तीन नर्स बर्खास्त

उपायुक्त बोले, प्रशासनिक सेवा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

फरीदाबाद। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने सिविल अस्पताल बादशाह खान में कार्यरत तीन नर्सों द्वारा एक महिला को गलत तरीके से डिलीवरी करने के मामले में सिविल सर्जन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों को नौकरी से टर्मिनेट करने के आदेश दिए हैं। सिविल अस्पताल में 25 अगस्त को तीनों नर्सों की लापरवाही के चलते एक महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई

25 दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

पलवल। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस सत्र में 25 दिव्यांग विद्यार्थियों को एपीजे अब्दुल कलाम कॉन्सॉर्टिक्स छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति के लिए 12 और 13 सितंबर को विद्यार्थियों को आवेदन करना होगा। चयनित होने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्च कॉन्सॉर्टिक्स द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के लिए कॉन्सॉर्टिक्स ने करीबन एक करोड़ रुपए की घोषणा की है। विश्वविद्यालय के अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर आर एच राठौड़ ने बताया कि इस योजना की पात्रता के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को दो दिन का समय दिया गया है। वह अपने संबंधित प्रमाण पत्र देकर इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं।

भाजपा ने दो मंत्रियों समेत सात विधायकों के टिकट काटे

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़
भाजपा द्वारा मंगलवार को जारी की गई 21 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में दो मंत्रियों व तीन मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया। पिछले से एक प्रत्याशी द्वारा टिकट वापस किए जाने के बाद आज वहां नए प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। भाजपा अब तक 90 में से 87 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा ने सिरसा, महेंद्रगढ़ तथा एनआईटी

चार हट्टे हुए नेताओं को दोबारा बनाया प्रत्याशी

दूसरी सूची में सबसे अधिक दलित चेहरे, दो मुस्लिमों को भी बनाया उम्मीदवार
फरीदाबाद सीटों को खाली छोड़ा हुआ है। भाजपा की पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी सर्वाधिक दलित चेहरे शामिल हैं। आज जारी की गई सूची में चार प्रत्याशी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं तो तीन जाट, तीन ओबीसी, तीन राजपूत, तीन पंजाबी, दो ब्राह्मण, एक सिख तथा दो मुस्लिम जाति से संबंधित हैं। भाजपा ने आज की सूची में दो महिलाओं को भी टिकट दिया है।

12 को नामांकन भरेंगे कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा

कुरुक्षेत्र। थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा 12 सितंबर को नामांकन पत्र भरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड़्डा अशोक अरोड़ा का नामांकन पत्र भरवाने के लिए आएंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरागी धर्मशाला से रोड शो के रूप में लघु सचिवालय पहुंचेंगे व आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने मंगलवार को बैरागी धर्मशाला में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान चुनावी कार्यालय में हवन किया गया।

पेरिस पैरालंपिक

भारत का शानदार प्रदर्शन

पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन भारतीय पैरा एथलीटों की दृढ़ता, साहस व अदम्य भावना का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, 'सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो अपने पूरे होने तक आपको जगाए रखते हैं।' पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम ने इसी भावना का परिचय दिया है। अडिग प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने यह दिखा दिया है कि अदम्य मानवीय इच्छाशक्ति से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, भले ही वह चाहे जितना बड़ा हो। भारतीय पैरा-एथलीटों के प्रदर्शन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत के बेटे और बेटियों में दुनिया की सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। अब तक की सबसे बड़ी 84 सदस्यों वाली टीम से भारत ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां छुई हैं और दुनिया को इस देश की खेल शक्ति पर गौर करने के लिए मजबूर किया है। यह असाधारण प्रदर्शन उनके द्वारा प्राप्त मैडलों की संख्या से आगे जाता है और खेल तथा दृढ़ता की वह भावना प्रकट करता है जो असंभव प्राप्त करने के लिए शारीरिक सीमायें तोड़ती है। पेरिस में भारत को मिले मैडल प्रतिभा और कठोर परिश्रम का परिणाम हैं। विभिन्न खेलों में मैडल प्राप्त करने से राष्ट्र गौरवान्वित हुआ है तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिली है। इनमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी व बैडमिंटन शामिल हैं। बिना हाथों के प्रतियोगिता में भाग लेने वाली माहिर तीरंदाज शीतल देवी ने अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व कौशल से सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने महिलाओं की संयुक्त तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। 'ट्रेक एंड फील्ड' एथलीट हेमेशा भारत का मजबूत पक्ष रहे हैं और उन्होंने रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। सुमित अंटिल ने जेवलिन श्रो में विश्व रिकार्ड बनाया है। रोडू की चोट से उबरने के बाद राइफल शूटर अविन लेखरा ने मैडल प्राप्त करने में सफलता पाई। इससे परता चलता है कि भारत परिवर्तनशील खेलों में मजबूत हो रहा है। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के पीछे उसकी अदम्य भावना है। हर पैरालंपिक खिलाड़ी के व्यक्तिगत साहस और दृढ़ता को अलग गाथा है, लेकिन पेरिस में ये सारी गाथायें एकसाथ मिल कर सीमायें तोड़ने के सामूहिक प्रयास में बदल गईं। विपरीत स्थिति में पशिक्षण से लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह तोड़ कर इन एथलीटों ने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्ची शक्ति शारीरिक क्षमताओं में न होकर मानसिक दृढ़ता में होती है। ऊंची कूद में निषाद कुमार जैसे एथलीट वित्तीय सीमाओं के बावजूद लगातार स्वयं को प्रशिक्षित करते रहे। इसी प्रकार पोलियो के कारण पैदा समस्याओं से जूझते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पेदले ने भारतीय टीम में अंतर्निहित संघर्ष क्षमता का परिचय दिया है। पेरिस में सफलता के पीछे बेहतरीन समर्थन और इस स्वीकार्यता की भावना है जो अंततः पैरा-एथलीटों को मिल रही है। सरकारी पहलों, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप तथा खेलों में समावेशन के प्रति बढ़ती जागरूकता ने ऐसा परिवेश बनाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है जहां दिव्यांग खिलाड़ी भी फल फूल सकते हैं। लेकिन पेरिस में सफलता केवल मैडल जीतने के बजाय वे सीमायें तोड़ना है जो भारत में पैरा-खेल प्राप्त कर सकते हैं। मरियप्पन थंगवेलू, देवेन्द्र झञ्जूरिया, और अन्य एथलीटों को प्रेरणादायक कहानियां यह विचार पैदा करती हैं कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है। भारतीय टीम के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में प्रदर्शित कर दिया है कि समावेशन, विविधता और सबके लिए अवसर पैदा करने को राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।



उन्होंने रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। सुमित अंटिल ने जेवलिन श्रो में विश्व रिकार्ड बनाया है। रोडू की चोट से उबरने के बाद राइफल शूटर अविन लेखरा ने मैडल प्राप्त करने में सफलता पाई। इससे परता चलता है कि भारत परिवर्तनशील खेलों में मजबूत हो रहा है। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के पीछे उसकी अदम्य भावना है। हर पैरालंपिक खिलाड़ी के व्यक्तिगत साहस और दृढ़ता को अलग गाथा है, लेकिन पेरिस में ये सारी गाथायें एकसाथ मिल कर सीमायें तोड़ने के सामूहिक प्रयास में बदल गईं। विपरीत स्थिति में पशिक्षण से लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह तोड़ कर इन एथलीटों ने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्ची शक्ति शारीरिक क्षमताओं में न होकर मानसिक दृढ़ता में होती है। ऊंची कूद में निषाद कुमार जैसे एथलीट वित्तीय सीमाओं के बावजूद लगातार स्वयं को प्रशिक्षित करते रहे। इसी प्रकार पोलियो के कारण पैदा समस्याओं से जूझते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पेदले ने भारतीय टीम में अंतर्निहित संघर्ष क्षमता का परिचय दिया है। पेरिस में सफलता के पीछे बेहतरीन समर्थन और इस स्वीकार्यता की भावना है जो अंततः पैरा-एथलीटों को मिल रही है। सरकारी पहलों, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप तथा खेलों में समावेशन के प्रति बढ़ती जागरूकता ने ऐसा परिवेश बनाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है जहां दिव्यांग खिलाड़ी भी फल फूल सकते हैं। लेकिन पेरिस में सफलता केवल मैडल जीतने के बजाय वे सीमायें तोड़ना है जो भारत में पैरा-खेल प्राप्त कर सकते हैं। मरियप्पन थंगवेलू, देवेन्द्र झञ्जूरिया, और अन्य एथलीटों को प्रेरणादायक कहानियां यह विचार पैदा करती हैं कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है। भारतीय टीम के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में प्रदर्शित कर दिया है कि समावेशन, विविधता और सबके लिए अवसर पैदा करने को राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। सुमित अंटिल ने जेवलिन श्रो में विश्व रिकार्ड बनाया है। रोडू की चोट से उबरने के बाद राइफल शूटर अविन लेखरा ने मैडल प्राप्त करने में सफलता पाई। इससे परता चलता है कि भारत परिवर्तनशील खेलों में मजबूत हो रहा है। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के पीछे उसकी अदम्य भावना है। हर पैरालंपिक खिलाड़ी के व्यक्तिगत साहस और दृढ़ता को अलग गाथा है, लेकिन पेरिस में ये सारी गाथायें एकसाथ मिल कर सीमायें तोड़ने के सामूहिक प्रयास में बदल गईं। विपरीत स्थिति में पशिक्षण से लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह तोड़ कर इन एथलीटों ने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्ची शक्ति शारीरिक क्षमताओं में न होकर मानसिक दृढ़ता में होती है। ऊंची कूद में निषाद कुमार जैसे एथलीट वित्तीय सीमाओं के बावजूद लगातार स्वयं को प्रशिक्षित करते रहे। इसी प्रकार पोलियो के कारण पैदा समस्याओं से जूझते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पेदले ने भारतीय टीम में अंतर्निहित संघर्ष क्षमता का परिचय दिया है। पेरिस में सफलता के पीछे बेहतरीन समर्थन और इस स्वीकार्यता की भावना है जो अंततः पैरा-एथलीटों को मिल रही है। सरकारी पहलों, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप तथा खेलों में समावेशन के प्रति बढ़ती जागरूकता ने ऐसा परिवेश बनाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है जहां दिव्यांग खिलाड़ी भी फल फूल सकते हैं। लेकिन पेरिस में सफलता केवल मैडल जीतने के बजाय वे सीमायें तोड़ना है जो भारत में पैरा-खेल प्राप्त कर सकते हैं। मरियप्पन थंगवेलू, देवेन्द्र झञ्जूरिया, और अन्य एथलीटों को प्रेरणादायक कहानियां यह विचार पैदा करती हैं कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है। भारतीय टीम के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में प्रदर्शित कर दिया है कि समावेशन, विविधता और सबके लिए अवसर पैदा करने को राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

कृषि निर्यात बढ़ाने का मार्ग

अद्यतन खाद्य प्रसंस्करण तकनीक तथा विश्व-स्तरीय गुणवत्ता मानकों का प्रयोग कर भारत अपने कृषि-निर्यात में काफी वृद्धि कर सकता है। इसके लिए प्रमुख वैश्विक फर्मों तथा एफपीओ के बीच साझेदारी विकसित करनी चाहिए।



ए.एस. मिश्र (लेखक, उद्योग जगत से संबद्ध हैं)

खेत से खाने की मेज तक सप्लाई श्रृंखला को गति देकर, वैश्विक व भारतीय खाद्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दे कर तथा खेतों पर ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दे कर किसानों को बेहतर मुनाफा सुनिश्चित करने के साथ ही फसल कटने के बाद होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस दिशा में नेतृत्वकारी भूमिका अदा करते हुए नई दिल्ली में 19-22 सितंबर तक 'वर्ड फूड इंडिया' का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही 2024-25 के केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र विकास के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस फंडिंग के माध्यम से जलवायु समस्याओं से निपटने तथा उत्पादकता, खोज एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

यह कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी है जिसमें 8 प्रतिशत गिरावट आई है। यह 2022-23 में 53.52 बिलियन डालर से घट कर 2023-24 में 48.9 बिलियन डालर रह गया। 2014-23 के बीच कृषि निर्यात औसतन केवल 2 प्रतिशत वार्षिक की गति से बढ़े। उल्लेखनीय है कि पांच उत्पाद-चावल, गेहूं, मांस, मसाले, चीनी तथा चाय-काफी का हिस्सा कुल कृषि उत्पाद निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक है। कभी-कभी घरेलू मांग पूरी करने तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए निर्यात पर नियंत्रण लगाया पड़ता है। हमारे कृषि निर्यातों का केवल 25 प्रतिशत प्रसंस्कृत या मूल्य-संवर्धित है। पिछले दशक में इस आंकड़े में लगभग कोई परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि, ज्यादा टेक-आधारित आपरेशनल आकार और उत्पादन क्षमता तथा विश्व बाजार में अंतरराष्ट्रीय मानक पूरा करने को देखते हुए यह काफी है। लेकिन 111 बिलियन प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यातक रिकॉर्डरलैंड की 'नेस्ले' जैसी कंपनियों की सफलता को देखते हुए स्पष्ट होता है कि तकनीक



और शोध के प्रयोग से क्या संभव हो सकता है। 9 बिलियन डालर टर्नओवर वाली उल्लेखनीय भारतीय घरेलू प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद बेचने वाली 'अमूल' आपरेशनल क्षमता, उत्पादन क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय मानक पूरा करने के मामले में नेस्ले से बहुत पीछे है। इसके बावजूद समुचित समर्थन और दृष्टिकोण के चलते वह भी ऐसी ही सफलता प्राप्त कर सकती है। प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का निर्यात लगभग 1 ट्रिलियन डालर वार्षिक है जिसमें 63 बिलियन डालर के साथ जर्मनी सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद 58 बिलियन डालर के साथ अमेरिका, 57 बिलियन डालर के साथ चीन तथा 50 बिलियन डालर के साथ फ्रांस का स्थान है। दक्षिणपूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के बड़े निर्यातक हैं।

हालांकि, मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली कृषि-निर्यात नीति लागू होने के बाद पिछले पांच साल में भारत के मूल्य-संवर्धित निर्यातों में 6.5 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है और यह कुल 15 बिलियन डालर तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद इससे वैश्विक रैंक में मामूली सुधार ही हुआ है और हम 21वें स्थान से ऊपर उठ कर 17वें स्थान पर पहुंच सके हैं। इस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में

कहा गया है कि भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 300 मिलियन टन उत्पादन के साथ यह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन भारत में प्रसंस्करण स्तर बहुत कम है। यह फलों के लिए 4.5 प्रतिशत, सब्जियों के लिए 2.7 प्रतिशत, दूध के लिए 21.1 प्रतिशत, मांस के लिए 34.2 प्रतिशत और मछलियों के लिए 15.4 प्रतिशत है। इसकी तुलना में चीन में प्रसंस्करण 25-30 प्रतिशत तथा पश्चिमी देशों में 60-80 प्रतिशत है।

प्रसंस्करण क्षमता में इस कमी के कारण भारत में उत्पाद का काफी हिस्सा बेकार चला जाता है। अनुमान है कि देश में फसल कटाई के बाद बरबादी का स्तर पूरी सप्लाई श्रृंखला में 18 से 25 प्रतिशत के बीच है, हालांकि फलों और सब्जियों के मामले में यह लगभग 45 प्रतिशत है। नीति आयोग का अनुमान है कि फसल कटाई के बाद लगभग 90,000 करोड़ रुपये की बरबादी होती है। इस स्थिति में सुधार के लिए खेतों पर ही समुचित छंटाई और ग्रेडिंग तथा प्रसंस्करण बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कृषि प्रोत्साहनों में परिवर्तन कर किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करना जरूरी है कि वे खेतों तथा उसके निकट बरबादी रोकने के प्रयास करें।

2020 में केन्द्र सरकार ने एक ट्रिलियन रुपये के कृषि ढांचागत फंड की घोषणा की थी ताकि कोल्ड चेन श्रृंखला

तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन ढांचा खेतों तथा फसल संग्रह केन्द्रों पर बनाने के लिए मध्यम से दीर्घकालीन अवधि की कर्ज फाइनेंसिंग की जा सके। तमिलनाडु द्वारा हाल ही में घोषित नई खाद्य प्रसंस्करण नीति में एक कदम आगे बढ़ कर बरबादी रोकने तथा कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं। इस नीति में कृषि उत्पादक संगठनों-एफपीओ तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता तथा केन्द्रीय योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पंजाब ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में प्रतिबद्ध एग्रीबिजनेस व खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव स्कीम-पीएलआईएसएफआई के लिए 2021-22 से 2026-27 के बीच 10,900 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतियोगी फर्मों को भारत में उत्पाद व कृषि निर्यात क्षेत्र में आकर्षित करना है। इस योजना का लक्ष्य प्रसंस्करण क्षमता में सुधार, भारतीय ब्रांडों को मजबूत करना, विश्व बाजार में उपस्थिति बढ़ाना, रोजगार सृजन तथा किसानों की आमदनी बढ़ाना है। मई, 2024 तक पीएलएसएफआई के 90 प्रतिशत धन का प्रयोग नहीं हुआ था।

सरकार ने 158 एसएमई लाभार्थियों को केवल 1,073 करोड़ रुपये दिए थे और इस प्रकार योजना का आधा समय बीत जाने के बावजूद उसका केवल 10 प्रतिशत धन प्रयोग हुआ था। इस प्रकार पैसे के बहुत कम प्रयोग से ज्यादा केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता उजागर होती है।

पीएलआई योजना का लक्ष्य वैश्विक प्रतियोगिता क्षमता तथा निर्यात बढ़ाना है। इसे देखते हुए एसएमई को वैश्विक स्तर पर स्थापित 'एंकर' फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने चाहिए। पिछले दशक में भारत ने शत प्रतिशत एफडीआई अनुमति के बाद 500 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई प्राप्त किया। इसे देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण को भारत का 'सनराइज उद्योग' समझा जाना चाहिए जो किसानों को प्रभावी रूप से लाभ दिलाए, एसएमई के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए तथा मूल्य-संवर्धन और उद्योग में समन्वय स्थापित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कृषि के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को रणनीतिक महत्व देना जरूरी है।

दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश देश के नाते हम धरती पर पर्यावरण दबाव का अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण मृदा क्षरण, जैवविविधता में कमी तथा जल संकट जैसे परिस्थितिकी मुद्दे सामने आ रहे हैं। व्यापक खाद्य व्यवस्थाओं में बरबादी रोकना जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। इससे खेतों से लेकर खाने की मेज तक खाद्य सप्लाई बेहतर करने में सहायता मिलेगी तथा हानिकारक उत्सर्जन घटेगा। खाद्य प्रसंस्करण की अद्यतन तकनीकों के प्रयोग, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानकों को मंजूर करने तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच खोलने के माध्यम से यह केन्द्रित रणनीति बड़ी वैश्विक फर्मों को आकर्षित कर हमारे लक्ष्य पूरे कर सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 'एपल' इस लक्षित दृष्टिकोण को सफलता का एक माडल है। यही माडल विभिन्न उद्योगों के लिए लागू किया जाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को समयबद्ध कार्यक्रम बना कर प्रमुख वैश्विक फर्मों के साथ कृषि उत्पादक संगठनों-एफपीओ तथा एसएमई के बीच साझेदारियों को बढ़ावा देना चाहिए।

संतुलित जीवन के लिये विश्राम जरूरी

ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, या यहां तक कि शांत सैर करना कुछ सरल अभ्यास हैं जो मन को साफ करने और संज्ञानात्मक स्पष्टता को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, कई लोग मानते हैं कि आराम सिर्फ रात को अच्छी नींद लेने तक ही सीमित है। यह पूरी तरह से गलत है। वास्तविक विश्राम जटिल है। शोधकर्ता समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में छह अलग-अलग प्रकार के आराम के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आराम के प्रत्येक रूप को अपनाकर, व्यक्ति अधिक संतुलित और ऊर्जावान जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दिमाग लगातार काम, सोशल मीडिया और दैनिक जिम्मेदारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं से भरा रहता है। इस चल रही स्थिति के साथ, मन अंततः थका और तनाव का शिकार हो

जाएगा। मन की शांति पाने के लिए, अपने दिमाग में विचारों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से खुद को अलग करना महत्वपूर्ण है। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, या यहां तक कि शांति सैर करना कुछ सरल अभ्यास हैं जो मन को साफ करने और संज्ञानात्मक स्पष्टता को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। नियमित रूप से ब्रेक लेने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपको रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है और निर्णय लेने की आपकी क्षमता में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इसमें आपके शरीर को शारीरिक परिश्रम से उबरने के लिए पर्याप्त समय देना शामिल है। स्वाभाविक रूप से, पर्याप्त आराम करना महत्वपूर्ण है, और यह हल्की शारीरिक गतिविधियों, स्ट्रेचिंग या मांसपेशियों के तनाव को कम करने के तरीकों के साथ अच्छी तरह से पूरक है। शारीरिक आराम विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सोना, योग अभ्यास करना या गर्म स्नान करना शामिल है। चोट की रोकथाम, मांसपेशियों

की रिकवरी और पूरे दिन ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर एक महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर देते हैं: हमारी भावनात्मक सीमाएं। हम अपने आस-पास के लोगों की संतुष्टि सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। भावनात्मक आराम अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और ईमानदारी से संबोधित करना शामिल है। जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हों और भावनात्मक थकावट के कगार पर हों, तो अपने शरीर को सुनना और आत्म-देखभाल को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अपने विचारों पर करीबी दोस्तों की चिकित्सक से चर्चा करना भावनात्मक सात्वना पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भावनात्मक अभिभूतता को रोकने के लिए इस प्रकार का आराम आवश्यक है और आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का ईमानदारी से जवाब देने में सक्षम बनाता है। दूसरों के साथ बातचीत करना आवश्यक है,

हालांकि यह काफी थका देने वाला हो सकता है। मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए, सामाजिक आराम में बड़ी सभाओं से दूर रहना और व्यक्तिगत भलाई पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अकेले या कुछ करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना आपको अपने सच्चे स्व के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जो थोड़ा-थोड़ा वाली जगहों पर अक्सर होने वाली उथली बातचीत के बजाय एकता या सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक आराम के पल ढूँढ़ने से हम जीवन के सार और हमें संतुष्टि देने वाली चीजों के साथ एक गहरा संबंध फिर से स्थापित कर पाते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए, इसका धार्मिक अर्थ हो सकता है, जबकि अन्य के लिए, यह प्रकृति, ध्यान और माइंडफुलनेस पर ज्यादा केंद्रित होता है। आध्यात्मिक आराम का अनुभव करने के लिए हमेशा एक विशिष्ट दिनचर्या या अनुष्ठान की

आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने से बड़ी किसी चीज से गहरा संबंध महसूस करने के बारे में है, जो शांति और सद्भाव को गहरी भावना ला सकता है। हमारे आधुनिक समाज में, किसी के लिए भी स्क्रीन और नोटिफिकेशन के जरिए हम पर बमबारी करने वाली भारी मात्रा में जानकारी और उत्तेजनाओं से बचना दुर्लभ है। विश्राम के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहना, रोशनी कम करना और कुछ शांति का आनंद लेना शामिल है। अपनी इंद्रियों को तरोताजा करने के लिए शांति के क्षणों को पुनः प्राप्त करें: एक अच्छी किताब पढ़ें, प्रकृति में डूब जाएं या ध्वनि की अनुपस्थिति में आनंद लें। आँखों, कानों और तंत्रिका तंत्र पर तनाव को कम करने के लिए आराम अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आराम के इन छह रूपों के बीच सामंजस्य को खोज करने से आप अपने आप को व्यापक रूप से तरोताजा कर पाएंगे, जिससे आप एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी पाएंगे।

आप की बात

राहुल की आदत
राजनीति में विफल रहने वाले राहुल गांधी विदेशों में भारत की छवि खराब करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। वास्तव में, राहुल की मंशा भाजपा को कोसने की रहती है, लेकिन भाजपा को कोसते-कोसते वह भारत को भी कोसना प्रारंभ कर देते हैं। इस बार अपनी अमेरिका यात्रा में वह भारत को कोसते हुए चीन की तारीफ कर रहे हैं। पिछले दस वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है और चीन को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हुए आर्थिक क्षेत्र में उसकी कमर तोड़ी है। भारत चीन को पीछे छोड़ कर आज दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन यह सब राहुल

उपद्रवियों पर लगाम
देश भर में त्यौहारों का समय चल रहा है। लेकिन कभी रतलाम तो कभी सूरत में या देश के किसी अन्य कस्बे, शहर में कतिपय उपद्रवी तत्वों द्वारा त्यौहारों की खुशहाली में विघ्न पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन तत्वों के खिलाफ समय रहते कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि, पुलिस और प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल भी रहता है। लेकिन ऐसे तत्व संक्रामक बीमारी की तरह देश में अराजकता पैदा करने को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे में गांवों, कस्बों और शहरों के मुहल्लों में शांति समितियां गठित करने व खुफिया पुलिस की निगरानी बढ़ाने के साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाने वाले भड़काऊ बयानों और फर्जी वीडियो पर लगाम लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि, ऐसे तत्वों में से कुछ अति-उत्साही व अराजक तत्व हो सकते हैं जो अपने अपराध के परिणाम न समझते हों। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक या चुनावी स्वार्थों के चलते कुछ राजनेता ऐसे तत्वों का मुखौटा या हथियार की तरह प्रयोग करें। ऐसे में इन निहित स्वार्थी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई सबसे जरूरी हो जाती है।
- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

अफजल गुरु की तारीफ
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए थी। उनका यह बयान अत्यन्त नदिनीय है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर अपराधी अफजल को फांसी न देते तो क्या उसे फूलों की माला पहनाते। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि यदि जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा जाता तो फांसी की अनुमति कतई न दी जाती। सभा जानते हैं कि अफजल गुरु ने देश की संसद पर हमले की साजिश रची थी। लोकतंत्र के इस मंदिर की सुरक्षा करते हुए हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस तरह अफजल गुरु की तारीफ कर रहे हैं वह भी एक

पैरालंपिक को प्रोत्साहन
पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन न केवल ऐतिहासिक, बल्कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। भारत ने कुल 29 मैडल जीते जिसमें सात स्वर्ण सिल्वर और 13 ब्रॉज मेडल हैं तथा कुल मिलाकर उसने 18वां स्थान प्राप्त किया। पैरालंपिक में दिव्यांग खिलाड़ी दुनिया भर के खिलाड़ियों से प्रतियोगिता करते हैं, जिनमें से अनेक को बेहतर सुविधायें मिलती हैं। इसे देखते हुए भारत की उपलब्धि बेमिसाल है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को भी इन सभी खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि जहां ऑलिंपिक खिलाड़ियों को 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ की राशि सरकारें देती हैं, दिव्यांग खिलाड़ियों को इतनी राशि नहीं दी जा रही है। यह विसंगति दूर की जानी चाहिए। इसके साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियां भी प्राथमिकता पर दी जानी चाहिए। जिला स्तर से दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलने वाले प्रोत्साहन से समाज में दिव्यांगता के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा में आज करेंगे सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ

● दुनिया भर के बायर्स और विजिटर्स लेंगे हिस्सा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ ग्रेटर नोएडा

बुधवार से ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे सेमीकॉन इंडिया 2024 को देखते हुए मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल इंडिया एक्सपो मार्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदर्शनी से लेकर आगंतुकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कार्यक्रम में पीएम मोदी की सहभागिता को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गौतम विश्वविद्यालय में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की।



सीएम योगी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के लिए निर्देश

उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में बुधवार से सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के बायर्स और विजिटर्स हिस्सा लेंगे। इसका शुभारंभ स्वयं पीएम मोदी करेंगे। इसी वैन्यू पर उत्तर

प्रदेश 25 से 29 सितंबर के बीच इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। मंगलवार शाम को सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रदर्शनी स्थल से लेकर विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सत्रों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें पूरे कार्यक्रम स्थल को मैप के

वैश्विक बाजार में यूपी की बढ़ती धाक का बनेगा माध्यम

लखनऊ/ ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार वैश्विक बाजार में अपनी बढ़ती धाक को और प्रशस्त करने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2024, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 2024 के साथ ही प्रोडक्ट्स इंडिया 2024 का भी आयोजन करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट व प्रोडक्शन के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के तौर पर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर के बीच यह आयोजन होने जा रहा है। कुल 35,000 स्केयर मीटर क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न पवेलियंस के माध्यम से यह आयोजन अद्भुत छटा बिखेरगा जिसमें दुनियाभर के 589 एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बढ़ते महत्व पर योगी सरकार का विशेष फोकस होगा और योगी सरकार प्रदेश के निवेश परक माहौल, गुड गवर्नंस के साथ ही सेक्टर फेवरेबल पॉलिसीज के प्रमोशन को सबसे ज्यादा महत्व दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश मोबाइल विनिर्माण उद्योग में अग्रणी है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैनुफैक्चरिंग में भी विशिष्ट योगदान रखता है।

सदैव स्मरणीय रहेंगे आंतरिक सुरक्षा के लिए गोविंद वल्लभ पंत के किए गए कार्य: योगी

● मुख्यमंत्री ने पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि

● कहा-जेल की यातना सही लेकिन आजादी के आंदोलन से कमी विचलित नहीं हुए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री रहे भारत रत्न, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर



पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कार्य किए वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों की आधारशिला रखने के लिए भारत के ऐसे महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी पावन जयंती पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अत्यंत ही यशस्वी रहा। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने

अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ दी और आजादी के आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए।

यही कारण था कि आजादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान, लगातार किए गए संघर्षों के कारण उन्हें स्वतंत्र भारत में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की, जिस पर आज का हमारा उत्तर प्रदेश आधारित है।

नोएडा को 'डायनामिक सिटी' बनाने के लिए गठित होगा टास्क फोर्स

● केवल औद्योगिक ही नहीं एडवांस्ड अर्बन एमिनिटीज वाले आधुनिक शहर के तौर पर भी पहचान को किया जाएगा मजबूत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ नोएडा

योगी सरकार ने नोएडा क्षेत्र के कलेक्टर को बदलने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

सीएम योगी का विजन है कि नोएडा को डायनामिक सिटी के रूप में पहचान मिले और केवल औद्योगिक ही नहीं बल्कि एडवांस्ड अर्बन एमिनिटीज वाले आधुनिक शहर के तौर पर उसकी ब्रांडिंग और

मजबूत हो सके। इस क्रम में नोएडा में वाइब्रेंट कल्चरल स्पेस को चिह्नित कर उनके विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस क्रम में प्रक्रिया शुरू करते हुए नॉलेज पार्टनर के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसके पूरा होने से टास्क फोर्स के गठन प्रक्रिया को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि टास्क फोर्स में

प्राधिकरण व जिला स्तर के विभिन्न अधिकारी भी शामिल होंगे और यह टास्क फोर्स विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर जारी कार्य को प्रोग्रेस रिपोर्ट, मॉनिटरिंग, डीटेल्स के संकलन से डाटाबेस निर्माण, निवेश के अवसर तलाशने, टूरिस्ट अट्रैक्शंस को डेवलप करने और क्षेत्र की रचनात्मकता बढ़ाने जैसे कार्यों को पूरा किया जाएगा। नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक महत्वपूर्ण

घटक है, जो औद्योगिक विकास और वैश्विक व्यापार को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने कई लाभ के बावजूद, नोएडा को शहजहंपुर का एस्पपी, 47 वीं वाहिनी पोएसी गाजियाबाद के सेनानायक सुधा सिंह को शंसी का एएसपी और शंकर को औरैया का एएसपी नयुक्त किया गया है। अलीगढ़ के एएसपी ग्रामीण पलाश बंसल को महोबा का एएसपी, कुशीनगर के एएसपी अभिनव त्यागी को एएसपी नगर गोरखपुर, अलीगढ़ के एएसपी अमृत जैन को अलीगढ़ में ही एएसपी ग्रामीण बनाया गया है।

राज्य कर विभाग ने जीएसटीआर में संशोधन करने की सुविधा प्रदान की

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने व्यापारियों के द्वारा दाखिल किए जाने वाले जीएसटीआर में संशोधन करने की सुविधा प्रदान किया है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं को उनके द्वारा पूर्व में दाखिल जीएसटीआर-1 रिटर्न को संशोधित किये जाने की सुविधा फॉर्म जीएसटीआर 1ए के माध्यम से प्रारंभ की गयी है। यह जानकारी राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने दी। उन्होंने बताया कि फॉर्म जीएसटीआर-1ए एक करदाता द्वारा किसी कर अवधि के लिए दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1 का एक संशोधन रिटर्न है जिसके द्वारा किसी माह विशेष के जीएसटीआर-1 में दाखिल किए गए किसी रिकॉर्ड में हुई गलती अथवा रिपोर्ट करने से छूट करण को उसी अवधि हेतु निर्धारित जीएसटीआर-1ए में संशोधित किया जा सकता है। बंसल ने बताया कि जीएसटीआर-1ए करदाता को जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि, के बाद उपलब्ध होगा। जीएसटीआर-1ए को समान कर अवधि हेतु जीएसटीआर 3 बी दाखिल करने से पहले किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म जीएसटीआर-1ए एक वैकल्पिक सुविधा है और इसे एक विशेष कर अवधि के लिए केवल एक बार दाखिल किया जा सकता है। जीएसटीआर-1ए में किए गए बदलाव करदाता जीएसटीआर 3 बी में स्वतः दर्ज हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि यदि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें,

सुल्तानपुर एकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र लखनऊ। विगत दिनों सुल्तानपुर सराफा लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव की एकाउंटर में मौत हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सारी परिस्थितियां एकाउंटर के फर्जी होने की तरफ इशारा कर रही हैं और पुलिस की जांच में कई कमियां सामने आ रही हैं। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अजय राय 9 सितम्बर, 2024 को स्वयं स्व. मंगेश यादव के परिजनों से मिलने उनके जौनपुर स्थित आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिस दौरान परिजनों से बात करके यह पता चला कि पुलिस ने 2 सितम्बर की रात मंगेश यादव को उनके घर से उठाया था और घर वालों से कहा था कि ये सुबह तक वापस आ जायेंगे। मगर 2 दिन बाद मंगेश की एकाउंटर में मौत हो गयी। मामले की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज से कराने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अग्रह किया है।

चकबंदी कार्यों में लेटलतीफी व अनियमितता पर चर अफसर निलंबित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सीएम योगी के निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर दो चकबंदी अधिकारियों समेत चार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र जारी किये गये हैं। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर महाराजगंज के ग्राम बैठवल्याय में प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने में अनियमितता पर सहायक चकबंदी अधिकारी अखिलेश चंद्र विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उप संचालक चकबंदी को अनियमितताओं को चक्रावृत्त करने में योगदान देने के लिए प्रत्येक चकबंदी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह चकबंदी आयुक्त ने बताया कि बिजनौर में चल रही चकबंदी में

अधिकारी शैलेन्द्र श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इसी ग्राम के संबंध में अनियमितताओं के लिए पूर्व में निलंबित सहायक चकबंदी अधिकारी अरुण नारायण सिंह के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने और तत्कालीन चकबंदीकर्ता कामता प्रसाद, संप्रति सहायक चकबंदी अधिकारी को अनियमितता के लिए निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। वहीं चकबंदी लेखपाल विकास सिंह, जो पूर्व से इसी ग्राम में अनियमितताओं के लिए निलंबित हैं, उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह चकबंदी अधिकारी राणा प्रताप (जो पूर्व से ही निलंबित हैं), उनके खिलाफ भी अतिरिक्त आरोप पत्र नित करने के निर्देश दिये गये। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि बिजनौर में चल रही चकबंदी में

कई के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई

अनियमितता को लेकर विभिन्न गांव के किसानों ने शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद निदेशालय स्तर पर समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में चकबंदी के दौरान अनियमितता की शिकायत सही मिलने पर तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी विजय कुमार, सप्रति बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मुजफ्फरनगर को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये। साथ ही उप संचालक चकबंदी को अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा गाँडा के बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी देवेंद्र सिंह को वार्डों के निस्तराण न करने एवं शिथिल पर्यवेक्षण पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने अपने यहां संबद्ध मौरजापुर के चकबंदी लेखपाल राजेंद्र कुमार

यादव द्वारा अनियमितताओं की शिकायत की थी। इस पर सम्बद्धीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए मौरजापुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को लेखपाल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। आजमगढ़ जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर चकबंदी कार्यों के शिथिल पर्यवेक्षण एवं कार्य में शिथिलता के दोषी चकबंदी अधिकारी (से.नि.) शैल राजीव कमल, सहायक चकबंदी अधिकारी (से.नि.) मोहन लाल श्रीवास्तव, राधेश्याम वर्मा, चक्रधर त्रिगुनाथ और जैनेंद्र प्रताप के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। मुजफ्फरनगर में चकबंदी कार्यों में अनियमितता पर चकबंदी अधिकारी तत्कालीन वीरेंद्र प्रकाश सप्रति सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ पिछले दस वर्ष से चल रही जांच रिपोर्ट अब तक निदेशालय को न दिये जाने पर जांच अधिकारी उप संचालक चकबंदी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की जरूरत : मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसपा मायावती ने अमेरिका में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के षडयंत्र में है। राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें,

जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षडयंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस फालतू बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान को आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। मायावती ने कहा कि ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कौटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको ईसाफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दी गयी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोविड-19 के प्रकोप के दौरान बंद कर दी गयी थी। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सीमा के खुलने से पर्यटक भारत तथा नेपाल के प्राकृतिक एवं रमणीक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे, इससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल के

कोविड महामारी के दौरान बंद हुई भारत नेपाल सीमा पर्यटकों के लिए खोली गई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दी गयी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोविड-19 के प्रकोप के दौरान बंद कर दी गयी थी। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सीमा के खुलने से पर्यटक भारत तथा नेपाल के प्राकृतिक एवं रमणीक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे, इससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल के

● सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मिलाती मजबूती: जयवीर सिंह

बीच स्थित धनगढ़ी और गौरीफांटा क्रासिंग दो वर्षों से बंद थी। गौरीफांटा-धनगढ़ी सीमा को फिर से खोला जाना प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष महत्व है। यह मार्ग विभिन्न परिदृश्यों तथा विविध वन्य जीवन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। यूपी के लखौमपुर जनपद में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन क्षेत्र है। घने जंगलों से घिरा यह इलाका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। हर साल बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी यहां पहुंचते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के धनगढ़ी शहर से लगा हुआ है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि भारत की ओर से नेपाल जाने के इच्छुक पर्यटकों को बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान

खासा आकर्षित करता है। नेपाल की सैर पर जाने वालों को बर्दिया उद्यान में बाघों और एक साँग वाले गैंडों की वृहद आबादी देखने को मिलती है। शुक्ला फांटा राष्ट्रीय पार्क लुभावने दृश्य और जैव विविधता का जीता-जागता उदाहरण है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा घास का मैदान है। वहीं, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, पर्यटकों की पहली पसंद है। यह घने जंगलों, वन्यजीव सफारी और अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लंबे समय बाद भारत और नेपाल के पर्यटकों को एक-दूसरे देश में फिर से जाने और घूमने का अवसर मिलेगा। नेपाल में मौजूद पर्यटन स्थल न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, बल्कि दोनों (भारत और

नेपाल) देशों के बीच आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रवेश द्वार भी है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गौरीफांटा-धनगढ़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बार फिर खुलना बौद्ध पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। यह मार्ग नेपाल से आने पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा सारनाथ, कुशीनगर जैसे पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा को अवसर प्रदान करता है। वहीं, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत है। बर्दिया, बौद्ध डेस्टिनेशन की रोमांचक यात्रा को प्रेरित करता है। इस द्विपक्षीय प्रवेश द्वार से निकट भविष्य में भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत की गहरी समझ विकसित होने की उम्मीद है।

चितन शिविर के बाद एवशन शिविर: असीम अरुण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय चितन शिविर का समापन मंगलवार को आगरा के एक निजी होटल में हुआ। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा केंद्र और राज्य की सामूहिक भागीदारी के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने समापन सत्र में विभिन्न राज्यों से हुए परामर्श एवं चिंतन के परिणामों को धरातल पर लागू कर अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्तियों के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने छात्रवृत्ति योजनांतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा छात्रवृत्ति योजनांतर्गत प्रस्तुति को सार रूप में उद्घृत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य मिल कर काम करेंगे तकनीकी कारणां से छात्रवृत्ति पाने से कोई भी छात्र वंचित न रह जाए।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए एआई का उपयोग करें एजेंसियां : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साइबर सुरक्षा एजेंसियों से आग्रह किया कि वे साइबर अपराधों से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग करें। लोगों की गाढ़ी कमाई को छपाने, फर्जी खबरें फैलाने और महिलाओं व बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने वाले अपराधियों के अपराध करने के तौर-तरीकों की पहचान के लिए एजेंसियां एआई का सहारा लें। यहां भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक डिजिटल लेन-देन में भारत की लगभग 46 प्रतिशत या लगभग आधी भागीदारी है, जिससे इन एजेंसियों का काम चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

2018 में स्थापित आई4सी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। इसका काम देश में साइबर अपराध से



संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना है। गृह मंत्री ने कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एआई का उपयोग करके अपराधियों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों की पहचान करें...इससे आपके साइबर अपराधों से लड़ने के नए तरीके खोजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश में इंटरनेट और

साइबर पहुंच किस प्रकार बढ़ी है। शाह ने कहा, 31 मार्च तक देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ रही, जबकि 2014 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या 25 करोड़ थी। साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आई4सी द्वारा बुधवार से शुरू किए जा रहे विशेष अभियान के दौरान राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 1930 को

लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। हमें इसके (साइबर अपराध के) खिलाफ और अधिक प्रयास करने की जरूरत है... हम एक बिंदु पर पहुंच गए हैं, लेकिन लक्ष्य अभी बहुत दूर है। साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताते हुए शाह ने कहा कि देश की प्रगत साइबर सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए यह जरूरी है कि सभी पक्ष मिलकर इस समस्या से निपटें। प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से कई तरह के खतरे भी पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अहम पहलू बन गई है। सरकार भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले पांच साल में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने और उन्हें तैयार करने की योजना बना रही है।

कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा, फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही नहीं

बेंगलुरु। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में कांग्रेस के कुछ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के गव्यपाल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस बीच ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस नेता नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तथा उनमें से कई ने खुले तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त भी की है। जब परमेश्वर से पूछा गया कि क्या पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान चल रही है, तो उन्होंने कहा, हर कोई संक्षम है, इसीलिए वे इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही कहाँ उठता है?

कोई सरकार कानून बनाए और दूसरी उसे निरस्त कर दे तो क्या कोई अनिश्चितता नहीं होगी : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब सरकार से सवाल किया कि क्या तब कोई अनिश्चितता नहीं होगी जब एक सरकार किसी वि्वि के लिए कानून लेकर आती है और अगली सरकार उसे निरस्त कर देती है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह सवाल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए किया जिसने खालसा वि्वि (निरस्त) अधिनियम, 2017 को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।

पीठ ने पंजाब की ओर से पेश वकीलों से पूछा, क्या तब अनिश्चितता नहीं होगी जब एक राजनीतिक दल सत्ता में आने पर वि्वि के लिए कानून बनाए और जब कोई अन्य राजनीतिक दल सत्ता में आए तो वह उसे (अधिनियम को) निरस्त कर दे?

पीठ ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खालसा विश्वविद्यालय और खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी ने उच्च न्यायालय के नवंबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का खूब किया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत खालसा विश्वविद्यालय का गठन किया गया तथा सोसायटी द्वारा पहले से चलाए जा रहे फार्मसी कॉलेज, शिक्षा कॉलेज और महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय में मिला दिया गया।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि 30 मई, 2017 को खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था और तत्पश्चात निरसन अधिनियम, 2017 पारित किया गया

था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश किए जाने के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि निरसन अधिनियम ेमनमाना है और पूरी कार्वाई संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करती है। पंजाब की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसमें कुछ भी मममाना नहीं है। राज्य के वकील ने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने 2016 में कानून बनाया था और 2017 में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने इस कानून को निरस्त कर दिया। शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार ने 2016 में खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था और केन्द्र अतिरिक्त सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। न तो किसी छत्र करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था और तत्पश्चात निरसन अधिनियम, 2017 पारित किया गया

प्रधानमंत्री पद टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालय ने शशि थरूर के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को रहत देते हुए उनकी प्रधामंत्री नेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई एक कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में एक निचली अदालत में कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया। थरूर को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार मंगलवार को यहां एक निचली अदालत में पेश होना था। पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया जाता है और कार सप्ताह में जवाब देने को कहा जाता है। इस बीच, आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।

थरूर ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही निरस्त करने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 29 अगस्त को शीर्ष न्यायालय का खूब किया था। सुनवाई के दौरान थरूर की ओर से पेश वकील मोहम्मद अली खान ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता को पीड़ित पक्ष नहीं कहा जा सकता और राजनीतिक दल के सदस्यों को भी पीड़ित पक्ष नहीं कहा जा सकता। खान ने कहा कि थरूर की टिप्पणी मानहानि कानून के प्रतिक्रिया खंड के तहत संरक्षित है, जो यह निर्धारित करता है कि अच्छी सोच के साथ दिया गया बयान अपराधिक नहीं है। उच्च न्यायालय ने अस्वीकार्य सीमाओं तक मानहानि के किसी मामले में पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा का विस्तार किया है। वकील ने कहा कि थरूर ने टिप्पणी करने से छह साल पहले कार्वां पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का संस्र्भ दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने हैरानी जताई कि 2012 में यह बयान अपमानजनक नहीं था जब लेख मूल रूप से प्रकाशित हुआ था। न्यायमूर्ति रॉय ने सुनवाई के दौरान कहा, आखिरकार यह एक रूपक है। मैं स समझने की कोशिश की है। यह उस व्यक्ति (मोदी) को अजेयता को दर्शाता है।

न्यायमूर्ति गौरी, चार अन्य को मद्रास हाईकोर्ट का स्थाई न्यायाधीश नियुक्त की सिफारिश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी और चार अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की मंगलवार को सिफारिश की। पिछले साल न्यायमूर्ति गौरी की उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले, बाबू के कई सदस्यों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके कथित नफरती भाषणों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव की बात कही थी। पिछले साल सात फरवरी को शीर्ष अदालत ने गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नियुक्ति के लिए एंटीडोपिंग द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने से पहले एक परामर्श प्रक्रिया हुई थी।

मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की तीन सदस्य उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने अदालत के स्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तीन महिलाओं सहित पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कॉलेजियम ने जिन पांच न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दी, वे हैं न्यायमूर्ति लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी, न्यायमूर्ति पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, न्यायमूर्ति कंधासामी कुलंदेवेलु रामकृष्णन, न्यायमूर्ति रामचंद्रन कलाईमथी और (5) न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन तिलाकवडी, स्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं। एक अन्य प्रस्ताव में, शीर्ष अदालत के तीन सदस्य कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कॉलेजियम ने जिन पांच उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतर सहयोगियों के परामर्श से इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश की। प्रस्ताव में कहा गया, उपरोक्त के महेन्द्रजर, कॉलेजियम यह सिफारिश करने का संकल्प लेता है कि न्यायिक अधिकारियों (1) आर. पूर्णिमा, (2) एम. जोतिरमण और (3) डॉ. ऑगस्टीन देवदास मारिया क्लेटे, को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाए। 23 अप्रैल, 2024 के प्रस्ताव में कुछ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश नहीं की गई है और उनके नामों की सिफारिश नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस कारण दर्ज किए गए हैं। तीन सदस्य शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने प्रस्ताव में कहा, इसलिए, हम उन्हें नरअसंदेज करने के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सहमत है।

तेईस अप्रैल, 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतर सहयोगियों के परामर्श से इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश की। प्रस्ताव में कहा गया, उपरोक्त के महेन्द्रजर, कॉलेजियम यह सिफारिश करने का संकल्प लेता है कि न्यायिक अधिकारियों (1) आर. पूर्णिमा, (2) एम. जोतिरमण और (3) डॉ. ऑगस्टीन देवदास मारिया क्लेटे, को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाए। 23 अप्रैल, 2024 के प्रस्ताव में कुछ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश नहीं की गई है और उनके नामों की सिफारिश नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस कारण दर्ज किए गए हैं। तीन सदस्य शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने प्रस्ताव में कहा, इसलिए, हम उन्हें नरअसंदेज करने के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सहमत है।

आदमखोर भेड़ियों के झुंड का पांचवा सदस्य पकड़ा गया, अब अल्फा की तलाश

भाषा। बहराइच

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के करीब 50 गांवों में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के झुंड में शामिल पांचवे भेड़िए को मंगलवार तड़के वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। अब वन विभाग को अल्फा नामक भेड़िए की तलाश है। बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आदमखोर भेड़ियों के झुंड के निशान दिखे। वहीं, कोंवां का झुंड भी दिखा। इसी बीच खबर आई कि पास के नथुवापुर गांव से एक पालतू बकरी गायब है। इससे यह तय हो गया था कि भेड़िए ने बकरी को उड़ाकर खाया है, और अब इनका जोड़ा यहीं कहीं आराम कर रहा होगा। उन्होंने कहा, यह करते-करते दैर शाम हो गई। शाम या रात में अभियान संभव नहीं था, इसलिए हम जाल, पिंजरा, खाबड़ (लकड़ी के फ्रेम वाला जाल), साधारण व थर्मल ड्रोन लेकर वहीं इनके मूवमेंट के इंतजार में बैठ गए। उन्होंने बताया, मंगलवार सुबह



चौथे भेड़िए को पकड़ा था। सिंह ने बताया, सोमवार शाम करीब छह बजे चक मार्ग पर हमें दो भेड़ियों के पैरों के निशान दिखे। वहीं, कोंवां का झुंड भी दिखा। इसी बीच खबर आई कि पास के नथुवापुर गांव से एक पालतू बकरी गायब है। इससे यह तय हो गया था कि भेड़िए ने बकरी को उड़ाकर खाया है, और अब इनका जोड़ा यहीं कहीं आराम कर रहा होगा। उन्होंने कहा, यह करते-करते दैर शाम हो गई। शाम या रात में अभियान संभव नहीं था, इसलिए हम जाल, पिंजरा, खाबड़ (लकड़ी के फ्रेम वाला जाल), साधारण व थर्मल ड्रोन लेकर वहीं इनके मूवमेंट के इंतजार में बैठ गए। उन्होंने बताया, मंगलवार सुबह

पांच बजे हमने अभियान शुरू किया। हमने कांबिंग शुरू की, पटखे चलाए और भेड़िए को जाल की तरफ ले जाने में कामयाब हो गए। करीब सवा छह बजे एक भेड़िया हमारे जाल में फंस गया। उसे हमने पिंजरे में कैद कर लिया। यह एक मादा भेड़िया है। उसका जोड़ीदार न भेड़िया मौके से भाग निकला है। जो भाग निकला है, शायद वही इस झुंड का मुख्य भेड़िया अल्फा है।

इस बीच अल्फा भेड़िए के लंगड़े होने की बात से अब वन विभाग पीछे हो रहा है। सिंह ने कहा, अभियान के बीच में कहीं पर झुंड में एक लंगड़ा भेड़िया होने की बात आ गई होगी लेकिन अब तक की गतिविधियों पर गौर करें तो लंगड़े भेड़िए की थ्योरी आधार हीन लग रही है। इन दिनों घान के खेतों में पानी भरा है, ऐसे में घान उठाकर रखने में एक पैर का दबाव अधिक हो सकता है। इसी वजह से संभवतः शुरुआत में कहीं से लंगड़े भेड़िए की बात आई होगी। उन्होंने कहा कि जब तक झुंड में शामिल आखिरी भेड़िया नहीं पकड़ लिया

जाता तब तक मुश्किल खत्म नहीं होगी।

प्रदेश की प्रमुख वन संरक्षक रेजू सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आज पकड़ी गई मादा भेड़िया को किसी चिड़ियाघर में भेजने की कोशिश की जाएगी। पकड़ी गई मादा भेड़िया आदमखोर है अथवा नहीं, इस सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि अवश्य ही आदमखोर होगी क्योंकि एक भेड़िए के आदमखोर होने पर पूरा झुंड ही मानवभक्षी हो जाता है। उन्होंने कहा, फिर भी वह आदमखोर है या नहीं इस सवाल पर अंतिम निष्कर्ष इसके व्यवहार को देखकर ही निकाला जा सकेगा। बहराइच की महसी तहसील के 50 गांवों में आतंक का कारण बने छह भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए पिछली 17 जुलाई से ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है। इन भेड़ियों के हमले में अब तक कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दो अन्य लोगों की मौत का कारण भी भेड़ियों का हमला ही बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है।

दलित लड़की का शील भंग करने की कोशिश में तासीन और शालिम गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा क्षेत्र में 16 वर्षीय दलित लड़की का शील भंग करने की कोशिश के आरोप में दो मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली राव ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा सिखेड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाए जाने के बाद सोमवार को तासीन और शालिम को गिरफ्तार किया गया। दोनों को उम्र 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने गत आठ सितंबर को नाबालिग लड़की का शील भंग करने की कोशिश की और उसके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी भी की। राव ने बताया कि आरोपियों ने लड़की को धमकी भी दी कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 78 (पीछा करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानसूझकर अपमान करना) और बाल वीर्य अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून तथा एएससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अधिवक्ता मोहिनी हत्याकांड के सभी छह आरोपी गिरफ्तार

भाषा। कासगंज

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक महिला वकील को कथित तौर पर अगवा करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक सभी छह आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि महिला वकील मोहिनी तोमर (40) पिछली तीन सितंबर को जिला अदालत से लापता हो गई थीं और एक दिन बाद उनका शव रेखपुर माइजर नहर से बरामद किया गया था। इस मामले में उनके पति बृजेंद्र ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि कासगंज थाने में वकील मुस्तफा कामिल, उसके तीन बेटों असद मुस्तफा, हैदर मुस्तफा और सलमान मुस्तफा और दो सहयोगियों मनाजिर रफी तथा केशव मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 103 (हत्या), 140 (1) (हत्या के इरादे से अपहरण या अपहरण), 62 (1) (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस

अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि वकील मुस्तफा कामिल और उसके तीन बेटों को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था, जबकि दो अन्य रफी और केशव को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कामिल और उसके दो बेटे हैदर और सलमान वकील हैं, जबकि असद अलीगढ़ में एलएलबी का छात्र हैं।

मोहिनी के पति बृजेंद्र के मुताबिक उनकी पत्नी को एक मुकदमे की पैरवी नहीं करने के लिए कामिल से धमकियां मिल रही थीं। पिछली तीन सितंबर को बृजेंद्र ने अपनी पत्नी को जिला न्यायालय में छोड़ दिया था, जहां से उन्हें आरोपियों ने अगवा कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। बृजेंद्र ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी ने हत्या के एक मामले में आरोपी मनाजिर रफी की जमानत का विरोध किया था। इसमें वह पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। मोहिनी की हत्या से अधिवक्ताओं के बीच आक्रोश फैल गया था और वकीलों ने न्याय की मांग कर दिया। कासगंज-बरेली राजमार्ग को अवरूद्ध कर दिया था। वकीलों ने पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है।

पेज 1 का शेष

हरियाणा ...

पटौदी (एससी) विधायक सत्य प्रकाश और गनौर विधायक निर्मल राणी को भी टिकट नहीं दिया गया है। अमित चंद मेहता ऐलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे, जहां से इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटालाचुनाव लड़ रहे हैं। निवर्तमान विधायक और हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली ने स्पष्ट कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय पार्टी की जीत अनिश्चित करने के लिए काम करेंगे, जिसके बाद राई विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण गल्लावत को मैदान में उतारा गया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने गनौर, पटौदी, हथीन और होडल सीटों से मौजूदा विधायकों को भी टिकट देने से इनकार कर दिया है। असंध से योगेंद्र राणा, गनौर से देवेन्द्र कौशिक और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को मैदान में उतारा गया है।

आईएफ...

के अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धारा

376 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई ह। मामले में चल रही जांच की पुष्टि करते हुए, वायु सेना अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि बडामा पुलिस स्टेशन से मामले की जांच के लिए संबंधित वायु सेना स्टेशन से संपर्क किया है। वायु सेना जांच में सहयोग कर रही है। महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना 31 दिसंबर, 2023 की रात को श्रीनगर के वायु सेना स्टेशन पर नए साल की पार्टी के दौरान हुई थी। महिला ने कहा कि पार्टी के बाद स्टेशन पर विंग कमांडर ने उससे पूछा कि क्या उसे उपहार मिला है। इसके जवाब में मैंने कहा कि कोई उपहार नहीं मिला है। उन्होंने मुझे अपने कमरे में आने के लिए कहा, जहां उन्होंने सभी उपहार रखे थे। वह उनके साथ उनके कमरे में चली गईं। महिला अधिकारी ने विंग कमांडर पर अपने कमरे में उसका यौन उपभोग करने का आरोप लगाया। पुलिस शिकायत में उसने कहा, वह इस घटना के बारे में दो महिला अधिकारियों को बताया। उन्होंने उसे शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी। वह इस माहौल में नई होने के कारण मानसिक सदमे में चली गईं। इस हद तक शर्मिदा और टूटी हुई थी कि रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह

अविवाहित लड़की होने के मानसिक दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, जिसने सेना में शामिल होने के बाद इस तरह के व्यवहार का सामना किया। चूंकि इस घटना और बुरे सपनों ने मुझे इस दुविधा में डाल दिया कि इस बारे में बात करूं या चुप रहूं, इसलिए आखिरकार लड़ने का फैसला किया। उसने आरोप लगाया कि उसे एओबी (एयर ऑफिसर कमांडिंग) को शिकायत दर्ज करने में भी परेशानी हुई और एक कर्नल को घटना की जांच करने का आदेश दिया और आरोपी को उसके साथ बैठाया गया। उसने आरोप लगाया कि अंतरिक जांच को ठीक से नहीं किया गया।

जीएनएसएस...

संबंध में एक पायलट अश्वयन कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर जीएनएसएस आधारित उपयोगकर्ता शूल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में एक

पायलट अश्वयन किया गया है।

बारामूला....

2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में है। वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। रशीद का नाम कश्मीरी व्यवसाई जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीरी घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्तपोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मस्जिद विवाद: हिंदू समूहों के बंद के आह्वान के बाद हिमाचल के संजौली में निषेधाज्ञा लागू

शिमला (भाषा)। संजौली इलाके में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बढ़ते तनाव और हिंदू संगठनों के बंद के आह्वान के मद्देनजर हिमाचल के संजौली में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है जिसमें बिना अनुमति के निर्माण कार्यव्यक्तिवों के एकर होने और लाठी, खंजर, डंडे, भाले और तलवार सहित घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाते का प्रावधान है।इच्छ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनुचित निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने बृहस्पतिवार को यहां चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और संजौली क्षेत्र में स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी। शिमला के जिलाधिकारी अनुपम कश्यप ने

बताया कि संजौली क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, सड़कें, राजमार्ग, फुटपाथ और पांचो से अधिक व्यक्तिवों के एकर होने और लाठी, खंजर, डंडे, भाले और तलवार सहित घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाते का प्रावधान है।इच्छ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनुचित निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने बृहस्पतिवार को यहां चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और संजौली क्षेत्र में स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी। शिमला के जिलाधिकारी अनुपम कश्यप ने

विहिप वी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बैठक में वाराणसी, मथुरा मंदिर विवाद, वक्फ विधेयक पर चर्चा

नई दिल्ली (भाषा)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा यहां आयोजित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बैठक में वाराणसी और मथुरा में मंदिरों से संबंधित विवाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, धर्मांतरण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। विहिप के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा सोमवार को आयोजित बैठक में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कम से कम 30 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। मेघवाल ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज मैंने विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित न्यायाधीश मिलन कार्यक्रम में भाग लिया और विकसित भारत के निर्माण के लिए न्यायिक सुधारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें भी पोस्ट करते हुए कहा, इस अवसर पर विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार की उपस्थिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अन्य न्यायविद, वरिष्ठ वकील और अन्य प्रख्यात बुद्धिजीवी उपस्थित थे। यह विहिप के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक आंतरिक बैठक थी, जिसमें वाराणसी और मथुरा के मंदिरों से संबंधित विवाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, गौहत्या और धर्मांतरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

